सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

राजधानी चौपाल

समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...

94169-26329
93068-13001

अंक : 12 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (22 से 28 मार्च 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

वित्तीय वर्ष : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

नई दिल्ली/हिसार (राजधानी चौपाल)| मार्च का महीना अपनी विदाई की दहलीज पर है और इसके साथ ही समाप्त हो रहा है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26। राजधानी के नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और निवेश प्रेमियों के लिए अगले 10 दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं हैं। यदि आपने अपनी वित्तीय डायरी के पन्ने अभी तक नहीं पलटे हैं, तो सावधान हो जाइए। 31 मार्च की समयसीमा (डेडलाइन) पत्थर की लकीर है, जिसे लांघने का मतलब है—भारी जुर्माना, टैक्स का अतिरिक्त बोझ और सरकारी योजनाओं के लाभ से हाथ धोना। 'राजधानी चौपाल' के इस विशेष अंक में हम उन अनिवार्य कार्यों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अब आपके पास समय बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम क्षणों में सर्वर डाउन होने या तकनीकी खराबी की आशंका बनी रहती है, इसलिए आज ही अपनी चेकलिस्ट दुरुस्त कर लें।

टैक्स बचत का अंतिम प्रहार: पुरानी व्यवस्था बनाम निवेश

देश में वर्तमान में दो प्रकार की कर प्रणालियां प्रभावी हैं। यदि आपने 'पुरानी आयकर व्यवस्था' का चयन किया है, तो आपकी टैक्स प्लानिंग का आधार धारा 80C है। इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवल 31 मार्च तक का समय है।

- **कार्य :** यदि आपका 1.5 लाख का कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो तुरंत LIC प्रीमियम, ELSS (म्यूचुअल फंड), PPF या NSC जैसे विकल्पों में निवेश करें।

धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाना न भूलें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा और भी अधिक है।

सुप्त खातों को जगाएं: PPF और सुकन्या समृद्धि योजना

सरकारी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश का सबसे बड़ा नियम अनुशासन है। इन खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

- **न्यूनतम सीमा:** PPF के लिए 500 और सुकन्या खाते के लिए 250 सालाना जमा करना जरूरी है।
- **जोखिम:** यदि आप 31 मार्च तक यह राशि जमा नहीं करते हैं, तो खाता 'फ्रीज' कर दिया जाएगा। इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको प्रत्येक चूक वाले वर्ष के लिए 50 का जुर्माना और बकाया राशि भरनी होगी।

कार्यालय में 'प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट' (POI) का खेल

नौकरीपेशा वर्ग के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वित्त वर्ष की शुरुआत में आपने अपने नियोक्ता (EMPLOYER) को एक घोषणा पत्र दिया था कि आप इतना निवेश करेंगे। अब उन दावों को साबित करने का वक्त है।

- **साक्ष्य:** जीवन बीमा की रसीदें, बच्चों की स्कूल फीस की रसीद, होम लोन का स्टेटमेंट और रेंट एग्रीमेंट (HRA के लिए) तुरंत एचआर विभाग को सौंपें।
- **नुकसान:** यदि आप समय सीमा के भीतर ये दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो कंपनी आपके मार्च के वेतन से भारी TDS काट लेगी, जिससे आपकी 'टेक-होम सैलरी' काफी कम हो सकती है।

होम लोन धारकों के लिए ब्याज प्रमाणपत्र

यदि आपने आशियाना बनाने या खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया है, तो आयकर की धारा 24 और 80C आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

- **कटौती:** होम लोन के ब्याज पर 2 लाख और मूलधन पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख तक की भारी टैक्स छूट का दावा आसानी से किया जा सकता है।
- **महत्व:** इसके लिए आपको बैंक से 'प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट' या बैंक स्टेटमेंट तुरंत डाउनलोड करना होगा। यह अनिवार्य दस्तावेज आपके निवेश के ठोस प्रमाण के तौर पर काम आता है और आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के समय भी इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है।

संशोधित रिटर्न: पुरानी गलतियों का सुधार

आयकर विभाग करदाताओं को अपनी पुरानी भूल सुधारने का एक सुनहरा अंतिम मौका देता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित है।

- **स्थितियां:** यदि आपके पिछले रिटर्न में आय की जानकारी अधूरी थी, या आप किसी महत्वपूर्ण निवेश को दिखाना भूल गए थे, तो यह अपनी त्रुटियों को सुधारने का बिल्कुल आखिरी अवसर है। इसके बाद पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाएगा और विभाग की ओर से दंडात्मक नोटिस आने की गंभीर संभावना बढ़ जाएगी। अतः समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर भारी जुर्माने से बचें।

विदेशी आय और फॉर्म 12B की अनिवार्यता

वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में कई लोगों के पास विदेशी स्रोत से आय होती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऐसी किसी भी आय और उस पर विदेशों में चुकाए गए टैक्स का विवरण 31 मार्च तक देना अनिवार्य है।

इसके साथ ही, यदि आपने इस चालू वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान नौकरी बदली है, तो अपनी पुरानी कंपनी की आय का विवरण फॉर्म 12B में भरकर नई कंपनी के पास जमा करें। ऐसा न करने पर टैक्स की गणना गलत हो सकती है और आपको अंत में अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान:

- **डिजिटल सावधानी:** ऑनलाइन निवेश करते समय केवल अधिकृत वेबसाइटों का ही उपयोग करें। 31 मार्च को सर्वर पर अत्यधिक दबाव रहता है, इसलिए ट्रांजेक्शन फेल होने का जोखिम रहता है।
- **बैंक छुट्टियां:** महीने के अंतिम सप्ताह में पड़ने वाली बैंक छुट्टियों की सूची पहले ही देख लें ताकि चेक क्लियरिंग में देरी न हो।
- **दस्तावेजों का मिलान:** निवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि रसीद पर आपका पैन नंबर सही दर्ज है, वरना टैक्स छूट का दावा खारिज हो सकता है।

अंतिम समय की भागदौड़ से बचें

विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय कार्यों को अंतिम 48 घंटों के लिए छोड़ना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। कई बार भारी ट्रैफिक से पेमेंट गेटवे जाम हो जाते हैं या केवाईसी अपडेट न होने के कारण आपका महत्वपूर्ण निवेश अटक जाता है। अतः राजधानी के जागरूक नागरिकों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे अगले 3-4 कार्य दिवसों में ही अपनी सभी फाइलें निश्चित रूप से निपटा लें। वित्तीय वर्ष का अंत केवल हिसाब-किताब का सामान्य समय नहीं है, बल्कि यह भविष्य की सुदृढ़ आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का सुनहरा मौका है। 31 मार्च 2026 तक इन सात अनिवार्य कार्यों को निपटाकर आप न केवल मानसिक शांति पाएंगे, बल्कि संभावित भारी आर्थिक दंड और कानूनी जटिलताओं से भी पूरी तरह मुक्त रहेंगे।

नियम पीछे, वसूली आगे... फॉर्म-6 के बिना ही स्कूलों ने बढ़ा दी फीस

फीस बढ़ाने से पहले देना होता है फॉर्म-6, विभाग कर रहा अभी पोर्टल पर फॉर्म भरवाने की तैयारी

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्कूलों में किताब वितरण में देरी के बाद अब निजी स्कूलों से फॉर्म-6 लेने और उसकी जांच की प्रक्रिया भी पटरी से उतरती नजर आ रही है।

स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग अभी तक एमआईएस पोर्टल पर फॉर्म-6 भरवाने का इंतजाम कर रहा है जबकि अधिकांश निजी स्कूल पहले ही नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ा चुके हैं। प्रदेश में करीब 10,701 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में स्कूलों ने महंगाई और बढ़ते खचर्चों का हवाला देते हुए नए सत्र के लिए 10 फीसदी तक फीस बढ़ा दी है।

नियमों के मुताबिक किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले फॉर्म-6 भरकर विभाग को देना अनिवार्य है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म-6 में दी गई जानकारी की जांच के लिए अधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं और गलत जानकारी देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है लेकिन अभी तक न तो समय पर फॉर्म 6 लिए गए और न ही फीस वृद्धि पर कोई रोक लग पाई।

अभिभावकों का कहना है कि विभाग की ढिलाई का सीधा नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। पानीपत के अभिभावक राजेंद्र कुमार और प्रदीप

गाहल्याण ने कहा कि अगर विभाग समय पर कार्रवाई करता तो स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल पाते। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विनीत गर्ग का दावा है अभी मार्च चल रहा है और जल्द ही फॉर्म-6 की प्रक्रिया निजी स्कूलों से पूरी करवाई जाएगी।

पिछले पांच वर्षों में फॉर्म-6 भरवाने में लेटलतीफी

पिछले पांच वर्षों में हरियाणा में फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया लगातार देरी का शिकार रही है। सत्र 2021-22 में अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी लेकिन कई स्कूलों ने मई-जून तक फॉर्म जमा किए थे। सत्र 2022-23 में भी पोर्टल मई के पहले सप्ताह तक ही खुल पाया था। सत्र 2023-24 में डेडलाइन 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई करनी पड़ी थी। सत्र 2024-25 में भी यही स्थिति रही थी। सत्र 2025-26 में अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करनी पड़ी फिर भी प्रक्रिया लंबित रही थी। वर्तमान में 18 मार्च तक फॉर्म-6 की कोई चर्चा तक नहीं है।

फरवरी-मार्च में पूरी हो जानी चाहिए प्रक्रिया: कुंडू

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वे भी विभागीय प्रक्रिया के कारण फंसे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यावान बान कुंडू के अनुसार विभाग जब तक पोर्टल नहीं खोलता तब तक स्कूल फॉर्म जमा नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया हर साल फरवरी-मार्च में पूरी हो जानी चाहिए जो अब तक लंबित है। यह प्रक्रिया फरवरी अंत तक पूरी हो जाए तो मार्च में निजी स्कूल नई फीस तय कर दाखिले शुरू कर सकते हैं।

अभिभावकों और स्कूलों पर असर

फॉर्म-6 लेने में देरी के कारण अभिभावकों पर बिना जांच के फीस का बोझ बढ़ गया है। स्कूलों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फीस में पारदर्शिता की कमी और विवाद की स्थिति बन रही है।

क्या है फॉर्म-6 और क्यों जरूरी है

फॉर्म-6 एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसे हर निजी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग को देना होता है। इसमें स्कूल को फीस बढ़ाने का कारण, स्टाफ की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, सुविधाओं और अन्य वित्तीय विवरण देना होता है। इसका उद्देश्य फीस वृद्धि को पारदर्शी और नियंत्रित रखना है। फॉर्म-6 पूरी तरह ऑनलाइन भरा जाता है। शिक्षा विभाग पोर्टल खोलता है जिस पर स्कूल लॉगिन कर जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारी अपलोड करते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा जांच और सत्यापन किया जाता है। विभाग की ओर से स्कूलों से फार्म छह लेने में देरी के कई कारण हैं। इनमें विभाग द्वारा पोर्टल समय पर न खोलना, प्रशासनिक लापरवाही और धीमी प्रक्रिया, पिछले सत्र की जांच लंबित होना आदि शामिल हैं।

अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट

ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा; भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| ट्रम्प प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका-इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें 110 डॉलर के पार निकल गई है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये 70 डॉलर के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनियाभर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है, उसे कम करने में मदद मिलेगी।

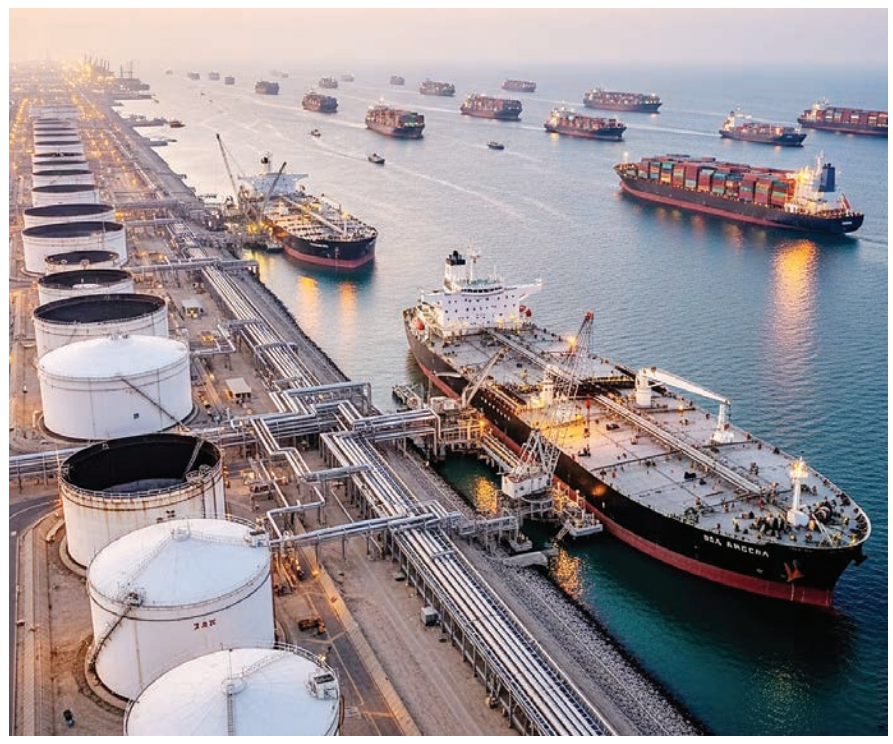

रूसी तेल की खरीद पर दूसरी बार प्रतिबंध हटाया : ट्रम्प प्रशासन ने गुरुवार को एक नया 'जनरल लाइसेंस' जारी किया, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, यह छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के 'सेंक्शंस वेवर' की जगह लेगा। पुराने लाइसेंस में कुछ तकनीकी स्पष्टता की कमी थी। नए लाइसेंस के जरिए उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया को इस छूट से बाहर कर दिया है।

युद्ध के कारण 120 डॉलर तक पहुंच गई थी तेल की कीमतें : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बीते दिनों ये 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल की कीमतों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' का बंद होना है। ये करीब 167 किमी लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है।

ईरान पर तेल प्रतिबंध मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था।

प्रदेश में महंगी होगी जमीन: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, एनसीआर के शहरों में सबसे ज्यादा उछाल की उम्मीद

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| प्रदेश में अपना आशियाना बनाने या जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे लोगों के लिए आने वाला नया वित्त वर्ष जेब पर भारी पड़ने वाला है। प्रदेश सरकार आगामी 1 अप्रैल से पूरे राज्य में नए कलेक्टर रेट लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। करीब 9 महीने के अंतराल के बाद सरकार एक बार फिर जमीनों के सरकारी भाव (कलेक्ट्रेट रेट) में संशोधन करने जा रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी की रजिस्ट्री फीस और प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ना तय है।

राजस्व विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, प्रदेश की 143 तहसीलों और उप-तहसीलों में नए रेट तय करने के लिए प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टरों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जमीनों की वर्तमान खरीद-फरोख्त और बाजार मूल्य का सटीक आकलन कर नई दरों का ड्राफ्ट पेश करें। सरकार का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर है जहाँ पिछले कुछ महीनों में विकास कार्यों के चलते जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछली बार 1 अगस्त को जब कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे, तो पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध और हंगामा हुआ था। तब जनता और प्रॉपर्टी कारोबारियों का आरोप था कि सरकार ने बिना किसी तार्किक आधार के और बेतरतीब तरीके से रेट बढ़ा दिए हैं। पिछली बार सरकार ने 'लेन-देन' के मूल्यों के आधार पर स्लैब तैयार किए थे, जिसमें 10% से लेकर 50% तक की भारी वृद्धि की गई थी। इस बार भी वैसी ही सुगबुगाहट ने प्रॉपर्टी बाजार में चिंता की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि बार-बार रेट बदलने से बाजार की स्थिरता प्रभावित होती है।

हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का साफ कहना है कि कलेक्टर रेट बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी का बोझ सीधे जनता पर आएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आगामी योजनाओं को लेकर पारदर्शिता बरती जाए ताकि निवेशक असमंजस में न रहें। वहीं, हरियाणा डीड राइटर एसोसिएशन के सदस्य बरखाराम ने तर्क दिया कि मात्र 9 महीने के भीतर दोबारा रेट बढ़ाना किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रेट बढ़ाना जरूरी भी है, तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम जनता पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

एनसीआर के शहरों में मचेगा 'हाहाकार'

इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की मार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे जिलों में पड़ने वाली है। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और नई टाउनशिप के कारण पिछले एक साल में संपत्तियों की रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त में भारी तेजी देखी गई है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इन शहरों में रिहायशी और कमर्शियल संपत्तियों के रेट में काफी बड़ा अंतर आ सकता है। अनुमान के मुताबिक, सामान्य रिहायशी क्षेत्रों में औसतन 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जबकि प्रमुख व्यावसायिक, औद्योगिक और प्राइम लोकेशन वाले क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा कहीं ज्यादा रहने की संभावना है। सरकार उन क्षेत्रों में रेट अधिक बढ़ाने के पक्ष में है, जहाँ बाजार मूल्य और वर्तमान कलेक्टर रेट के बीच एक लंबा फासला बना हुआ है।

राजस्व में बढ़ोतरी का लक्ष्य

हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े गवाही देते हैं कि प्रदेश में रजिस्ट्री से होने वाली आय साल-दर-साल बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहाँ लगभग 7.40 लाख रजिस्ट्रियों से 8,882 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, वहीं 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों में यह बढ़कर 12,322 करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना है। स्पष्ट है कि सरकार इस राजस्व को और बढ़ाना चाहती है।

राजस्व विभाग के अधिकारी के अनुसार, सभी तहसीलों को कलेक्टर रेट से संबंधित ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की योजना इन नई दरों को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से ही लागू करने की है, ताकि राजस्व संकलन में निरंतरता बनी रहे और सरकारी खजाने में वृद्धि हो सके। अब देखना यह होगा कि 1 अप्रैल को घोषित होने वाले अंतिम रेट मध्यम वर्ग को कितनी राहत देते हैं या फिर यह फैसला विवादों का नया दौर शुरू करता है।

अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मिलेगा मातृत्व अवकाश

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में मंगलवार का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने मातृत्व और वात्सल्य की उन बेड़ियों को काट दिया है, जो अब तक 'दिनों और महीनों' के गणित में उलझी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक युगांतरकारी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मातृत्व अवकाश केवल उन महिलाओं का अधिकार नहीं है जो तीन महीने से कम उम्र के शिशु को गोद लेती हैं, बल्कि यह हर उस माँ का हक है जिसने परिवार पूरा करने के लिए 'गोद लेने' का रास्ता चुना है, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' की धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। अब तक यह कानून कहता था कि यदि कोई महिला 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो वह मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं होगी। कोर्ट ने इस प्रावधान को 'मनमाना' और 'भेदभावपूर्ण' बताते हुए कहा कि यह कानून उस बुनियादी भावना को समझने में विफल रहा कि एक माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक सेतु बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उम्र की नहीं।

जैविक और दत्तक माँ में कोई भेद नहीं : राजधानी के विधि विशेषज्ञों के बीच इस फैसले की सबसे अधिक चर्चा जस्टिस पारदीवाला की उस टिप्पणी को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा कि "जैविक माँ और दत्तक माँ के बीच कोई अंतर नहीं है।" कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि गोद लेना भी प्रजनन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। माँ और बच्चे के बीच के संबंध को इस आधार पर नहीं तौला जा सकता कि बच्चा कोख से जन्मा है या उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए जीवन में लाया गया है।

अदालत ने जोर देकर कहा कि मातृत्व संरक्षण का उद्देश्य बच्चे के आगमन के तरीके से नहीं बदलता। एक बड़ा बच्चा जब किसी नए परिवार में आता है, तो उसे छोटे शिशु की तुलना में नए माहौल, नए चेहरों और नई दिनचर्या में ढलने के लिए माँ के साथ और भी अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में उसे अवकाश से वंचित करना बच्चे के अधिकारों का भी हनन है।

गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा। पीठ ने कहा कि दत्तक माता-पिता और बच्चे, दोनों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल के लिए शुरुआती समय ही नहीं मिलेगा, तो उस बच्चे का विकास और परिवार की नींव कमजोर रह जाएगी।

गुरुग्राम में दस औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी नहीं मिलने से डीजल की खपत बढ़ने की संभावना

डीजल महंगा होने से उद्योगों की उत्पादन लागत पांच फीसदी बढ़ेगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| डीजल महंगा होने से जिले के 500 उद्योगों की उत्पादन लागत पांच प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे उद्यमियों को नुकसान होने की चिंता सता रही। उद्योगों के मशीनों, कारखानों, बॉयलर और बड़े जेनरेटरों में उपयोग होता है। औद्योगिक संगठनों ने कहा कि जिले में औद्योगिक डीजल की यहां बहुत डिमांड नहीं है, लेकिन पीएनजी नहीं मिलने से डीजल की खपत बढ़ जाएगी, जिससे उद्योगों के उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। कुछ उद्यमी पांच सौ से एक हजार लीटर डीजल खरीदते हैं।

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (पीएफटीआई) के चेयरमैन दीपक मैनी ने कहा कि औद्योगिक डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोत्तरी का असर अब विभिन्न उद्योगों पर पड़ने की संभावना बढ़ाई है। डीजल महंगा होने से उद्योगों के सामने दो ही विकल्प बचे हैं या तो उत्पादन लागत को खुद वहन करें या फिर उत्पादों की कीमत बढ़ाएं। बड़ी निर्माण कंपनियां, जो भारी मात्रा में औद्योगिक डीजल खरीदती हैं, वे फिलहाल लागत का आकलन कर रही हैं। लंबे समय तक बढ़ी हुई कीमतों को झेल पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में कीमतों में पांच प्रतिशत तक वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है।

नए प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य को रोकना पड़ेगाः अमेरिका-ईरान युद्ध से लोहे की महंगाई से रियल एस्टेट सेक्टर पर मार पड़ी है। इसमें लोहे के दाम दो प्रतिशत बढ़ने से निर्माण लागत में भारी इजाफा हुआ है। गुरुग्राम में 150 से अधिक बड़े प्रोजेक्ट्स पर लागत बढ़ने से कार्य धीमा हुआ। बिल्डर्स ने बढ़ती लागत के चलते 18 से 20 नए

प्रोजेक्ट लॉन्च टालने की बात कह रहे है। वहीं घर खरीदारों पर भी बढ़े दामों का असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। बीएस रियल स्टेट कंपनी के एमडी केके सिंह ने कहा कि देशों के बीच हो रहे युद्ध ने महंगाई बढ़ा दी है। लोहे के दाम बढ़ने से निर्माण लागत बढ़ने से खरीदारों को भार पड़ना स्वाभाविक है। कुछ दिनों के लिए नए प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य को रोकना पड़ रहा है।

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम चंद शर्मा ने कहा कि अभी जो डीजल दाम बढ़ा है। यह डीजल वाहनों में इस्तेमाल नहीं होता है। साधारण डीजल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टरों पर सीधा असर पड़ेगा।

निर्माण कार्य पर असर पड़ेगा : कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र के ऑटोमोबाइल उद्यमी कश्मीर सिंह ने कहा कि सरिया, लोहा आदि के दाम बढ़ने के आसारऔद्योगिक डीजल के महंगा होने का सीधा असर निर्माण कार्य पर पड़ सकता है। सीमेंट से लेकर सरिया, लोहा, एल्यूमिनियम समेत अन्य निर्माण सामग्री महंगी हो सकती है। यदि साधारण डीजल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान के दाम भी बढ़ने की आशंका है। यदि डीजल की कीमतों में यह बढ़ोतरी बनी रहती है, तो आने वाले समय में उत्पादों के दाम तीन से पांच प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ सकते हैं।

स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कीमतें बढ़ेंगी : रियल स्टेट विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आयात-निर्यात की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट के फ्लैटों की कीमत दो से पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती है। कई बिल्डर्स ने नए प्रोजेक्ट को लांच नहीं करने का विचार कर रहे हैं। लागत बढ़ने से कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट में निर्माण में खर्च बढ़ा है तो स्वयं वहन करेगा। क्योंकि खरीदार बिल्डर को निर्माण लागत बढ़ने का पैसा नहीं चुकाएगा।

चार हजार करोड़ के निवेश से जापान की कंपनी बैटरी ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में चार हजार करोड़ रुपये के निवेश से हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। जापानी कंपनी की ओर से नए उद्योग लगाने के लिए पेशकश की गई है। यह कंपनी एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट (प्लांट) स्थापित करना चाहती है।

इसके पहले टीडीके कंपनी ने सोहना आईएमटी में एक प्लॉट स्थापित कर रखा है। शनिवार को जापानी कंपनी टीडीके के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के दौरान निवेश करने करने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट-2026 के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय

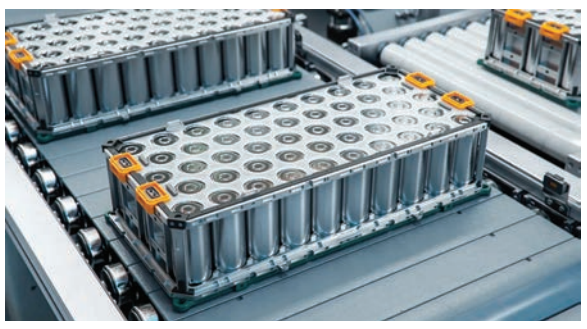

ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ जापानी कंपनी टीडीके के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में करीब चार हजार करोड़ रुपये निवेश कर नया प्लॉट बनाने की इच्छा जताई है। कंपनी यहां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट स्थापित करना चाहती है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी, टीडीके बिजनेस के सीईओ फुमिओ शशिदा, टीडीके एनर्जी से हिदेआकि सेकी, डिवाइस से ताकाहिरो सुतो, काजुनोबू मियाके आदि मौजूद रहे।

आईएमटी 1600 एकड़ पर विकसित की जा रही : सोहना आईएमटी 1600 एकड़ पर विकसित की जा रही है। इसमें 180 एकड़ पर टीडीके कंपनी का 3,000 करोड़ रुपये का लिथियम-आयन बैटरी प्लांट है। मोबाइल/वियरेबल उपकरणों के लिए इसमें बैटरी पैक बना है। सबसे बड़ी लिथियम-आयन बैटरी निर्माण इकाई, जो भारत की 40% मोबाइल बैटरी की मांग को पूरा करने की क्षमता रखती है। कंपनी में सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। अब चार करोड़ करोड़ से नई कंपनी स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की वैश्विक सप्लाई चेन को और मजबूत करने पर कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और नीति समर्थन को मजबूत किया जा रहा है, जिससे हरियाणा को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। इन सभी कार्यों का समन्वय 'विदेशी सहयोग विभाग' द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां यह विदेश सहयोग विभाग पूरी तरह से कार्यरत है।

कार्रवाई : मासूम से दरिंदगी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आवाज उठाई

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| एक पॉश सोसाइटी में तीन साल की बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच सीबीआई या फिर एसआईटी से करवाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई होने के बाद शनिवार को गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई। इसके बाद एक दंपति और एक घरेलू सहायिका को गिरफ्तार कर लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान एक दंपति निवासी पश्चिम-बंगाल और उनकी सहेली निवासी एटा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। ये तीनों वर्तमान में गुरुग्राम के गांव घाटा की झुग्गियों में रह रहे थे और इनकी उम्र 30 से 32 वर्ष के बीच है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया इस घटना का सही समय और तारीख नहीं बताई गई थी। पीड़ित बच्ची की बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग और मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें पुलिस को प्राथमिक तौर पर कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों का मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला है। इस आधार पर जांच करते हुए कई अन्य धाराएं भी जोड़ी गई थी। आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

चार फरवरी को दर्ज हुआ था यह मुकदमा

बच्ची के पिता की शिकायत पर सेक्टर-53 थाने में चार फरवरी को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया गया था। पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच सोसाइटी में काम करने वाली दो महिला नौकरानी और एक अन्य व्यक्ति ने उनकी तीन वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें और यौन शोषण किया। पिता का आरोप था कि गुहार लगाने के बावजूद पुलिस मामले में जांच नहीं कर रही थी।

आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में फ्रेंच-जर्मन की पढ़ाई होगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से जिले के सरकारी स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यह पहल न केवल नई शिक्षा नीति को मजबूती देगी, बल्कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार शुरुआत में इस योजना को जिले के चयनित स्कूलों के तहत संस्कृत मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय और पीएम श्री स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर जर्मन भाषा में दक्ष बनाने पर जोर रहेगा, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भाषा शिक्षा मिल सके।

बेसिक स्तर पर विदेशी भाषा सिखाई जाएगीः छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम के साथ विदेशी भाषा की कक्षाएं दी जाएंगी। शुरुआत में बेसिक स्तर से भाषा सिखाई जाएगी, जिसमें बोलचाल, उच्चारण और दैनिक उपयोग पर फोकस रहेगा। धीरे-धीरे इसे एडवांस स्तर तक ले जाया जाएगा, ताकि छात्र भाषा को व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल कर सकें।छात्रों को इससे कम उम्र में ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान हासिल कर पाएंगे, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप और विदेशों में पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भाषा के साथ-साथ छात्रों का आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल और सोचने का दायरा भी विकसित होगा।

मिलेनियम सिटी की सड़कों को धूलमुक्त करने की तैयारी, इन सड़कों को मॉडल बनाया जाएगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने 400 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब 285 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों को धूल-मुक्त बनाना, हरियाली बढ़ाना और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, ताकि पर्यावरण और ट्रैफिक दोनों में सुधार हो सके।

नई सड़कों को सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां स्वच्छता, हरियाली और सुव्यवस्थित यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़कों के

किनारे हरित पट्टियां विकसित होंगी, नियमित मशीनी सफाई होगी और जल निकासी की मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अलग लेन तैयार की जाएगी। अवैध पार्किंग से जाम की समस्या खत्म करने के लिए वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थान भी विकसित किए जाएंगे। सिंगापुर की तर्ज पर बनने वाली इन सड़कों में उच्च गुणवत्ता निर्माण, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, धूल नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शहर की समग्र छवि और जीवन स्तर बेहतर होगा।

इस योजना के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें बस स्टैंड, सेक्टर-10, पटौदी रोड, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और खेड़की दौला क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सीमा से सटे सेक्टर-39, 32, पालम विहार, नाथूपुर और सेक्टर-21 सहित कई इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सीक्यूएम के निर्देश पर शहर की 400 किलोमीटर सड़कों को दोबारा से विकसित किया जाएगा। ताकि इन सड़कों को धूल मुक्त किया जा सके। इसको लेकर योजना तैयार कर ली है। अधिकतर सड़कों को मॉडल सड़क बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

न्यूज ब्रीफ

खेल नर्सरी : 50 की प्रक्रिया ही आगे बढ़ी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| जिले में खेल नर्सरी योजना को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 172 आवेदन मिलने के बावजूद अब तक केवल 50 नर्सरियों की ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। इसकी मुख्य वजह विभाग द्वारा फिलहाल सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देना माना जा रहा है। खेल विभाग ने अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों, स्टेडियमों और पंचायतों से आए आवेदनों पर कार्रवाई शुरू की है। इन नर्सरियों का जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन कर उनकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जा चुकी है। वहीं निजी खेल अकादमियों से जुड़े आवेदनों पर अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे उनमें असमंजस बना हुआ है। जिला खेल अधिकारी आरती सोलंकी ने बताया कि फिलहाल सरकारी संस्थानों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राइवेट नर्सरियों के संबंध में जैसे ही निर्देश मिलेंगे, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जिले में पहले से 21 खेल नर्सरियां संचालित हैं। नई के शुरू होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा देरी के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

खेल नर्सरी : 50 की प्रक्रिया ही आगे बढ़ी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| जिले में खेल नर्सरी योजना को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 172 आवेदन मिलने के बावजूद अब तक केवल 50 नर्सरियों की ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। इसकी मुख्य वजह विभाग द्वारा फिलहाल सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देना माना जा रहा है। खेल विभाग ने अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों, स्टेडियमों और पंचायतों से आए आवेदनों पर कार्रवाई शुरू की है। इन नर्सरियों का जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन कर उनकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जा चुकी है। वहीं निजी खेल अकादमियों से जुड़े आवेदनों पर अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे उनमें असमंजस बना हुआ है। जिला खेल अधिकारी आरती सोलंकी ने बताया कि फिलहाल सरकारी संस्थानों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राइवेट नर्सरियों के संबंध में जैसे ही निर्देश मिलेंगे, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जिले में पहले से 21 खेल नर्सरियां संचालित हैं। नई के शुरू होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा देरी के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी

सोहना (राजधानी चौपाल)| एक अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने दो सख्त शर्तें लागू की हैं। अब किसान केवल वैध पंजीकृत नंबर वाले वाहन से ही फसल मंडी ला सकेंगे, बिना नंबर वाले वाहन पर पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही, मंडी गेट पर फसल पंजीकरण के समय किसानों को बायोमेट्रिक के तहत अंगूठे का निशान देना अनिवार्य किया गया है, ताकि भुगतान सीधे आधार-लिंक बैंक खाते में हो सके। इससे बिचौलियों पर रोक लगेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। मार्केट कमेटी सोहना के चेयरमैन दयाराम लोहिया और सचिव दिनेश श्योकंद ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

वोकेशनल कोर्स : छात्र अब केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी सीख सकेंगे

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| वोकेशनल कोर्स से जुड़े छात्र अब केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क के जरिए वास्तविक कौशल भी सीख सकेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शुक्रवार को जारी बजट से गुरुग्राम सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्किल आधारित शिक्षा को मजबूती मिलेगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वो छात्र, जो विभिन्न वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें अपने विषयों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा।

जिले के करीब 80 स्कूल इस योजना में शामिल हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, फिजिकल एजुकेशन, रिटेल, बैंकिंग एवं फाइनेंस और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जैसे विषयों के लिए करीब एक करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। यह राशि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदने पर खर्च होगी। वोकेशनल कोर्स का उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलेगा, जो नौकरी या स्वरोजगार में सहायक होगा। हालांकि आईटी, कृषि, सिलाई, ब्यूटी थेरेपी, सिक्योरिटी, टूरिज्म, प्लंबिंग और पावर जैसे कुछ कोर्स के लिए फिलहाल बजट जारी नहीं किया गया है।

एजेंसी पर गैस न होने का नोटिस लगाने से परेशानी

गुरुग्राम/सोहना (राजधानी चौपाल)| शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर की कमी से परेशानी कम होने का नाम ले रही है। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की आपूर्ति कम होने से परेशान है। वहीं, सोहना में एजेंसी की खिड़की पर गैस न होने का नोटिस लगा दिया। सिलेंडर की आपूर्ति होने की सूचना के लिए दो मोबाइल नंबर जारी कर दिए गए।

जिले के 20 भारत गैस एजेंसियों पर कंपनी से सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई। वहीं सोहना में भारत गैस एजेंसी को आपूर्ति न होने के कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिले। शनिवार को स्थानीय अनाज मंडी में स्थित भारत गैस एजेंसी के कार्यालय से सैंकड़ों उपभोक्ता को खाली लौट गए। जिसका मुख्य कारण फरीदाबाद के गांव प्याला

में स्थित गैस प्लांट से शनिवार को गैस की आपूर्ति न होना बताया गया। उपभोक्ता रोजाना की तरह से शनिवार को भी गैस कार्यालय पर पर्ची कटवाने के लिए सुबह 7 बजे से आना शुरू हो गए थे। लेकिन कार्यालय सुबह 9 बजे खुलने के साथ ही खिड़की पर गैस न होने का नोटिस लगा दिया गया।

नोटिस के साथ दो मोबाइल नंबर जारी किए हुए। उक्त मोबाइल नंबरों पर गैस की आपूर्ति होने की जानकारी प्राप्त करने को कहा गया। गैस एजेंसी के अनुसार शनिवार से पहले एक दिन में उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने का आंकड़ा 600 से 900 पहुंच गया था। लेकिन शनिवार को पूरे दिन में 200 के करीब उपभोक्ता बिना सिलेंडर की पर्ची कटाकर घरों को लौट गए।

प्याला प्लांट से सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई : सोहना भारत गैस एजेंसी मैनेजर अनिल शर्मा ने कहा कि शनिवार को उन्हें प्याला प्लांट से सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई। जिसके कारण शनिवार को एक भी सिलेंडर की पर्ची नहीं बनाई गई। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दो मोबाइल नंबर जारी कर दिए है। जैसे ही गैसे की आपूर्ति होगी। वैसे ही उपभोक्ताओं फोन के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक गुरुग्राम के अशोक कुमार ने बताया कि भारत गैस एजेंसियों पर कंपनी की ओर से सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होने से दिक्कत आई है। इंडेन-एचपी कंपनी की ओर से सिलेंडरों की आपूर्ति एजेंसियों पर हुई है।

मिलेनियम सिटी में बारिश से पारा गिरा, प्रदूषण से भी राहत मिली

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मिलेनियम सिटी में शुक्रवार को रुक-रुककर रिम-झिम बारिश होती रही। इससे पारा गिर गया। वहीं, कई दिन प्रदूषित हवा से भी लोगों को राहत मिली। हालांकि, दूसरी ओर कई स्थानों पर हुए जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी।

बारिश के बाद बड़ी ठिठुरन ने एक बार फिर मार्च महीने में जनवरी की याद दिला दी। मार्च के महीने में आमतौर पर पंखे और एसी चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुक्रवार की बारिश ने मौसम में ऐसी ठिठुरन पैदा की कि लोगों को मजबूरन फिर से अलमारी से गर्म कपड़े निकालने पड़े। ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। मार्च के महीने में इस तरह की ठंड और बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.09 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 15.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह से दोपहर 12 बजे तक बारिश हो रही थी। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड अनुसार दोपहर तक जिले में पांच एमएम के लगभग बारिश हुई।

अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन 26 मार्च को रवाना होगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पात्र बुजुर्ग लाभार्थियों को निःशुल्क तीर्थ स्थानों पर यात्रा 26 मार्च से शुरू हो रही है। पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए 26 मार्च को विशेष ट्रेन चलाई जा रही है।

22 मार्च तक यात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा करने के लिए www.saralharyana.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के लिए पात्र लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके अलावा उसकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए। पहली विशेष ट्रेन 26 मार्च को अंबाला से रवाना होगी। इस ट्रेन में गुरुग्राम के पंजीकृत यात्री दिल्ली से सवार हो सकेंगे। यह विशेष ट्रेन 26 मार्च को दोपहर 03:00 बजे अंबाला स्टेशन से रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा करने वाले सभी लाभार्थियों को अपने साथ आधार कार्ड, दो फ़ोटो लेकर आना अनिवार्य है।

शहर में भूजल हर साल पांच फीट तक नीचे खिसक रहा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मिलेनियम सिटी में भूजल स्तर हर साल तीन से पांच फीट नीचे खिसक रहा है। वर्ष 2021 में 30.55 मीटर से घटकर 2024 में 30.07 मीटर पहुंच गया है। भूजल स्तर कम होना सोसाइटियों, कॉलोनियों से लेकर सेक्टरों में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होना है। इसके कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भूजल का उपयोग सबसे अधिक निर्माण कार्यों में हो रहा है।

गुरुग्राम नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता रमन शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल से जलापूर्ति करने से भी भूजल स्तर गिरता है। विभागों के पास पानी की सप्लाई करने का संशाधन ठीक नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 350 ट्यूबवेल विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए हैं। गर्मियों के दिनों में इन ट्यूबवेलों से जलापूर्ति की जाती है।

वर्ष 2009 में गुरुग्राम का भूजल स्तर 25.74 मीटर था और वर्ष 2018 में 36.4 मीटर तक पहुंच गया था। वर्ष 2021 में 30.55, वर्ष 2022 में 30.73, वर्ष 2023 में 30.70 और 2024 में 30.07 पहुंच गया है। हर साल से जलस्तर घट जा रहा रहा है। हर साल औसत भूजल स्तर 7.57 मीटर गिर रहा है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में पानी की उपलब्धता पर असर डालेगी। जो गुरुग्राम के लिए चिंता का विषय है। गुरुग्राम शहर डार्क जोन (बहुत कम भूजल स्तर वाला इलाका) घोषित किया जा चुका है। यहां के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। मौजूदा 404 रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत करने की बात कही जाती है। लेकिन हर बारिश में यह काम नहीं करते हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड चिंता जता चुका

गुरुग्राम में भूजल के गिरते स्तर पर केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूए) की ओर से गंभीर चिंता जताई थी। बोर्ड की ओर से 6 नवंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा गया था कि गुरुग्राम में हर साल 43,262.85 हैक्टेयर मीटर (एचएएम) भूजल का दोहन हो रहा है, जबकि जिले में उपलब्ध वार्षिक भूजल संसाधन महज 20,333.39 हैक्टेयर मीटर ही हैं। जिला अपनी क्षमता से करीब दोगुना भूजल निकाल रहा है। शहरी क्षेत्र में भूजल दोहन का स्तर 326.52 फीसदी तक पहुंच चुका है। इसमें भूजल रिचार्ज की तुलना में तीन गुना से अधिक पानी निकाला जा रहा है, जो बेहद खतरनाक संकेत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी है।

हिसार के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड; राख हुआ करोड़ों का सामान

हिसार (राजधानी चौपाल) |शहर के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हिसार में शनिवार की काली रात एक बड़े हादसे की गवाह बनी। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लास्टिक पाइप और इलेक्ट्रिकल सामान के एक विशाल गोदाम में लगी भीषण आग ने न केवल उद्यमी की मेहनत को राख कर दिया, बल्कि शहर के फायर फाइटिंग सिस्टम के उन खोखली दावों की भी पोल खोल दी, जिन्हें प्रशासन अक्सर फाइलों में दुरुस्त बताता है।

शनिवार रात करीब 10:15 बजे, जब शहर की रफ्तार थमने लगी थी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया से उठती आग की लपटों ने आसमान को सुर्ख लाल कर दिया। अर्बन एस्टेट निवासी अंकित गर्ग के प्लास्टिक पाइप और बिजली के उपकरणों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। प्लास्टिक के जलने से निकलने वाले काले धुएं और जहरीली गैसों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आनन-फानन में मालिक को सूचित किया गया। गनीमत यह रही कि गोदाम का शटर खुलते ही सबसे पहले अंदर खड़ी कीमती फॉर्च्यूनर गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा धमाका और भी भयानक हो सकता था।

इस अग्निकांड ने प्रशासन के आपदा प्रबंधन के दावों पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर तैनात थीं, लेकिन विडंबना देखिए कि जब चार गाड़ियों का पानी खत्म हुआ, तो उन्हें दोबारा पानी भरने के लिए शहर के दूसरे छोर पर स्थित फायर स्टेशन जाना पड़ा। राजधानी चौपाल की पड़ताल में सामने आया कि औद्योगिक क्षेत्र और शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में एक भी क्रियाशील फायर हाइड्रेंट नहीं है। दमकल की गाड़ियों को पानी भरने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। इस आवाजाही में जो समय बर्बाद हुआ, उसी दौरान आग ने अपना दायरा और बढ़ा लिया। यदि मौके पर ही पानी की व्यवस्था होती, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था।

मानवता की मिसालः जब मजदूर और आम जन बने फायर फाइटर

जहाँ सरकारी तंत्र पंगु नजर आया, वहीं स्थानीय लोगों और श्रमिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पास की फैक्ट्रियों के श्रमिक अपनी नींद छोड़कर मदद के लिए दौड़े। एक स्थानीय कैंटीन संचालक ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन सभी ने मिलकर सुरक्षित रखे सामान पर पानी डाला और उसे वहां से हटाया। दमकल विभाग के डिप्टी फायर ऑफिसर साहिल और सीनियर कर्मी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में 15 जांबाज कर्मचारियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद जान की बाजी लगाकर आग को रिहायशी इलाके की ओर बढ़ने से रोका। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी मौके पर मुस्तैद रही, जो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी।

अनसुलझे सवाल और प्रशासन की जिम्मेदारी

अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी विजय पाल पुलिस बल के साथ देर रात तक मोर्चा संभाले रहे। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडस्ट्रियल एरिया में फायर एनओसी की नियमित जांच होती है? करोड़ों का टैक्स देने वाले इस क्षेत्र में प्रशासन फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया? क्या हम केवल तब जागेंगे जब कोई बड़ी जनहानि होगी?

जिले की 5 तहसील और 4 उपतहसील में 8002 इंतकाल पेंडिंग, हिसार-हांसी में 3885 तो कंप्यूटर में फीड ही नहीं

रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़वाने के लिए भटक रहे लोग

हिसार (राजधानी चौपाल) | जिले में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के बाद मालिकाना हक के लिए सरकारी रिकॉर्ड (इंतकाल/म्यूटेशन) में नाम दर्ज करवाना लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आलम यह है कि जिले की 6 तहसील और 3 सब-तहसीलों में 8,002 इंतकाल लंबित हैं। नियम कहते हैं कि रजिस्ट्री के 13 कार्य दिवस में इंतकाल हो जाना चाहिए, लेकिन यहां महीनों से फाइलें दबी हुई हैं। सबसे ज्यादा पेंडेंसी हिसार और हांसी तहसील में है, जहां लोग तहसीलदारों और पटवारियों के चक्कर काट रहे हैं। हिसार तहसील की बात करें तो 4469 जबकि हांसी में 1626 इंतकाल पेंडिंग हैं।

कहां, किस स्तर पर अटकी फाइलें जिले में रोज औसतन 250 से अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले इंतकाल की रफ्तार बेहद सुस्त है। कंप्यूटर फीडिंग : 3,855 इंतकाल ऐसे हैं जो अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सिस्टम में दर्ज ही नहीं किए हैं। 4,747 इंतकाल स्वीकृति के लिए पटवारी, कानूनगो और तहसीलदारों के पास लंबित हैं। 3,059 मामले ऐसे हैं जो कंप्यूटर में तो फीड हो गए, लेकिन 10 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी अधिकारियों ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए।

देरी यानी धोखाधड़ी को सीधा आमंत्रण जमीन के मामलों में हो रहे फर्जीवाड़े के पीछे इंतकाल में देरी एक बड़ी वजह है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक रजिस्ट्री के बाद इंतकाल दर्ज नहीं होता, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का ही नाम बोलता है। इसका फायदा उठाकर जालसाज एक ही प्लॉट या जमीन को कई खरीदारों को बेचकर ठगी करते हैं। अगर रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल हो जाए, तो रिकॉर्ड अपडेट होने से ऐसे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

डीसी ने दिया अल्टीमेटम मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी महेंद्र पाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी अपने-अपने कार्यालयों के सभी पेंडिंग इंतकाल दर्ज किए जाएं। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं।

इंतकालों की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर तहसील में शनिवार को शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पटवारी और तहसीलदार इंतकालों के काम को पूरा कराते हैं। शनिवार को लगाए गए शिविरों में इंतकाल किए गए। डीसी ने भी निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

न्यूज ब्रीफ

सीसवाल गांव में छात्राओं ने किया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल)| गुरु द्रोणाचार्य गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने सीसवाल गांव में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया। इस दौरान छात्राओं ने घर-घर जाकर लोगों से उनकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य सामाजिक पहलुओं से संबंधित जानकारी एकत्रित की। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की प्राचार्या डॉ. अमिता ग्रेवाल ने छात्राओं को कहा कि इस प्रकार के सर्वेक्षण शिक्षा को व्यवहारिक रूप से समझने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और इस तरह के कार्यों में बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गांव के लोगों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।

गेट 2026 परीक्षा में आशिष ने पाया पहला रैंक

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल)| शांति निकेतन पब्लिक स्कूल मंडी आदमपुर के पूर्व छात्र आशीष ने गेट 2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। आशीष ने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 1 तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल कर विद्यालय, क्षेत्र और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। गेट परीक्षा से देश के शीर्ष संस्थानों में उच्च शिक्षा एवं सरकारी उपक्रमों में चयन होता है। इस शानदार उपलब्धि के आधार पर आशीष को अब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी एवं आई आईएससी में पीएचडी करने का अवसर मिलेगा, साथ ही इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी जैसी प्रमुख संस्थाओं में कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न फेलोशिप एवं स्कॉलरशिप का भी लाभ मिलेगा। विद्यालय के चेयरमैन पपेन्द्र ज्याणी, वाईस चेयरमैन डॉ. युद्धवीर बैनीवाल, डायरेक्टर अनिरुद्ध बिश्नोई तथा प्रिंसिपल राजेंद्र ने आशीष की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण एवं विद्यालय की मजबूत शैक्षणिक नींव का परिणाम है।

बच्चों का मानसिक रुप से मजबूत व भावनात्मक रुप से संतुलित होना अत्यंत आवश्यक : राजपाल

हिसार (राजधानी चौपाल)| दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट द्वारा दिग्विजय मेमोरियल स्कूल, कैमरी में मानसिक स्वास्थ्य व कौशल विकास पर शिक्षक प्रशिक्षण विषय पर महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उनके जीवन कौशल के विकास हेतु प्रभावी तकनीकों से अवगत कराना था। इस अवसर पर दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट के संयोजक राजपाल सिंह बासनीवाल ने अपने विस्तृत संबोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह गया है। बच्चों का मानसिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

आर्थिक कमजोर परिवारों को प्रदान की जा रही सहायता राशि

हिसार (राजधानी चौपाल)| हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।

डीसी महेंद्र पाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद परिवारों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। इसके तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपए अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे कम हो) की शादी के लिए 51 हजार रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) उन्हें 41 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। उपायुक्त ने सभी पात्र परिवारों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।

पति का अपमान नहीं सह सकीं सती, स्वयं को कुंड में समर्पित कर दिया

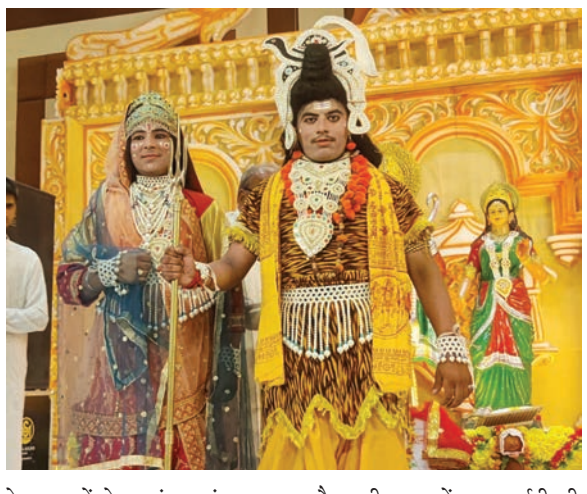

हिसार (राजधानी चौपाल)| श्री रामलीला कमेटी कटला द्वारा आयोजित 129वें श्री रामनवमी महोत्सव के दूसरे दिन सती चरित्र और भगवान शिव के प्रसंगों का ऐसा भावपूर्ण वर्णन हुआ कि पूरा पंडाल भक्ति और भावनाओं से सराबोर हो उठा। जैसे ही कथा व्यास भावेश कृष्ण भारद्वाज ने सती चरित्र का प्रसंग शुरू किया, पूरा पंडाल शांत होकर कथा में डूब गया। उन्होंने संवाद शैली में कहा जब पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तब सती का हृदय व्यथित हो उठा... कुछ क्षण रुककर उन्होंने भावुक स्वर में कहा सोचिए... एक ओर पिता का घर, दूसरी ओर पति का सम्मान... और सती ने क्या चुना...? पंडाल में बैठे श्रद्धालु एकटक मंच की ओर देखने लगे। फिर कथा व्यास ने कहा सती ने अपने आत्मसम्मान और भगवान शिव के गौरव के लिए यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया... यह त्याग नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यह सुनते ही कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। वातावरण में सन्नाटा छा गया, फिर हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कथा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कलियुग में भगवान का रूप नहीं दिखता तो क्या हुआ... नाम तो है... नाम का स्मरण करो... नाम में ही भगवान का साक्षात रूप बसता है...। जिस जिह्वा से राम' निकला... समझो वहां स्वयं भगवान प्रकट हो गए...। इस दौरान शिव-पार्वती विवाह की भव्य झांकी निकाली गई। त्रिशूल धारण किए भगवान शिव और सजीव रूप में माता पार्वती की झलक पाकर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए।

21 मार्च को मनु प्रसंग और श्रीराम जन्मोत्सव, 22 मार्च को बाल लीला व राम विवाह तथा 23 मार्च को वन गमन, केवट प्रसंग और भरत चरित्र का मंचन होगा। 27 मार्च को भव्य शोभायात्रा और विशाल भंडारे के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा।

भाजपा व कांग्रेस ने खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ाया : राजेन्द्र सोरखी

हांसी (राजधानी चौपाल)| आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हरियाणा में गत दिवस हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए नंगा नाच दिखाने का काम किया। प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों के कारनामों पर आश्चर्यचकित है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र सोरखी ने कहा कि जगजाहिर है कि राज्यसभा के चुनाव में विधायकों की बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त हुई। दोनों पार्टियों ने प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जिसका आने वाले समय में हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करना सीधा-सीधा भ्रष्टाचार की ओर संकेत देता है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने व मामला ईडी को देने की मांग की है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ता धारी भाजपा जो हर समय बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करती है, आज उनका भी चेहरा बेनकाब हो गया है।

लुवास के वैज्ञानिकों ने सीखे जूनोटिक बीमारियों से निपटने के गुर

हिसार (राजधानी चौपाल)| लुवास के वैज्ञानिकों ने नई दिल्ली के नैस कॉम्प्लेक्स में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। मॉक ड्रिल्स में पहचानी गई कमियों को दूर करना विषय पर केंद्रित इस वर्कशॉप में वैज्ञानिकों को सिखाया गया कि भविष्य में अगर कोई महामारी या जैविक खतरा आता है तो अलग-अलग विभाग मिलकर कैसे काम करेंगे।

लुवास से डॉ. राजेश, डॉ. विजय जाधव, डॉ. स्वाति दहिया और डॉ. मनेश कुमार ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में देशभर के पशुपालन विभागों, लैब और रिमाउंट वेटरनरी कोर के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने एवियन इन्फ्लूएंजा बर्ड फ्लू के सिमुलेशन के जरिए समझाया कि संक्रमण फैलने पर विभागों के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। वैज्ञानिकों को राज्य और केंद्र स्तर पर वन हेल्थ गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जानकारी दी गई। इसका मकसद जैविक खतरों और संभावित जैव आतंकवाद से निपटने के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करना है। जल-जनित रोगों के प्रकोप के दौरान त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी संचार का अभ्यास कराया गया।

नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के निदेशक ब्रिगेडियर एमएम रामचंद्र ने तकनीकी सत्रों का संचालन किया। उन्होंने बताया कि जूनोसिस जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए केवल मेडिकल नहीं, बल्कि पशु चिकित्सा और सुरक्षा एजेंसियों का आपसी समन्वय सबसे जरूरी है। लुवास के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कार्यशाला बेहद उपयोगी रही। इसमें सीखी गई तकनीकें भविष्य में जूनोटिक रोगों के प्रकोप को रोकने और पब्लिक हेल्थ को सुरक्षित रखने में मील का पत्थर साबित होंगी। इससे आपदा प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय की क्षमता बढ़ी है।

राजकीय कॉले में कंप्यूटर विभाग में कार्यशाला संपन्न, विद्यार्थियों ने सीखे कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम

हिसार (राजधानी चौपाल)| गुरु गोरखनाथ राजकीय कॉलेज में हारट्रोन एडवांस स्किल सेंटर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग तथा प्लेसमेंट सेल ने एक सप्ताह की कार्यशाला की। इस दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ते हुए कंप्यूटर आधारित पाइथन प्रोग्रामिंग एवं कैनवा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे उन्हें नई तकनीकों को समझने और व्यावहारिक रूप से सीखने का अवसर मिला। कार्यशाला के समापन समारोह में अग्रोहा के राजकीय कॉलेज प्राचार्य डॉ. पवित्र मोहन मुख्यातिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु गोरखनाथ राजकीय कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विवेक सैनी ने की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करती हैं और उन्हें नई तकनीक सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, जो भविष्य में रोजगार प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती हैं।

मुख्यातिथि डॉ. पवित्र मोहन ने कहा कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि आधुनिक तकनीक ने युद्ध की प्रकृति को भी बदल दिया है परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और यह मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राचीन ब्राह्मी लिपि को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर कार्यशाला के इंचार्ज सतीश वर्मा ने एडवांस स्किल सेंटर के निदेशकों एवं ट्यूटरों का विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यशाला के संयोजक डॉ. प्रवीण बिश्नोई ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उपप्राचार्य राजेंद्र सेवदा, श्वेता, रजनी, सत्येंद्र, गोविल जिंदल, कमलेश ख्यालिया, राजपाल, दीपिका, सुदेश, कुमारी सरोज एवं आशुतोष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. मुकेश कुमार ने किया।

क्रॉस वोटिंग मामला... जवाब की जांच के लिए बुलाई जाएगी अनुशासन समिति की बैठक

कांग्रेस ने पांचों विधायकों से 7 दिन में मांगा जवाब, हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के मामले में कांग्रेस के पांच विधायकों से सात दिन में जवाब मांगा गया है। इन विधायकों को नोटिस भेजा गया है। जब नोटिस का जवाब मिल जाएगा, तब पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें विधायकों पर लगे आरोप और उनके जवाब का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद अनुशासन समिति की ओर से रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। पार्टी हाईकमान से निर्देश मिलने के बाद ही विधायकों पर कार्रवाई होगी।

अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक का कहना है कि जवाब का इंतजार है। किसी को दोबारा नोटिस नहीं भेजा जाएगा, जो वे जवाब देंगे और उन पर जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच होगी। यदि दोषी पाए जाते हैं तो पार्टी से निष्कासित किए जा सकेंगे। हालांकि पार्टी के संविधान को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर, इस बारे में अनुशासन समिति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात कर सकती है, क्योंकि वे ही राज्यसभा चुनाव के दौरान मौजूद थे। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके हैं कि पांच विधायकों ने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है।

चुनाव में भाजपा ने खरीदे वोट, कांग्रेस ने बेचेः अर्जुन

रोहतक इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि वास्तविकता जनता के सामने है कि किस तरह से भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में खुला बाजार लगाकर विधायक खरीदने के लिए बोली लगाई और कांग्रेस ने किस तरह से अपने विधायकों को बेच दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेना संगठन का फैसला था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बने कर्मबीर बौद्ध को अभय सिंह चौटाला का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस संगठन ने तो बौद्ध को बेच दिया था, लेकिन ना चाहते हुए उनकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस केवल भूपेन्द्र सिंह हुडा है और भाजपा के हाथों चुनाव में बिक कर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अब हुड्डा बचाने में लगे हुए हैं। अर्जुन

चौटाला शनिवार को रुपया चौक स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। इससे पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और 23 मार्च को नरवाना में शहीदी दिवस पर होने वाले इनेलो युवा सम्मेलन को लेकर निमंत्रण भी दिया।

सूत्रों का कहना है कि इस मामले में हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने नई दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ बात की है। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हाईकमान को क्रॉस वोटिंग को लेकर सूचित कर दिया है। अब पार्टी हाईकमान को अनुशासन समिति की रिपोर्ट का इंतजार है, संभव है कि यह रिपोर्ट 31 मार्च से पहले हाईकमान के पास पहुंच जाएगी

कांग्रेस विधायक गोकुल बोले- मुझे न धमकी मिली, न ही प्रलोभन : सिरसा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद सिरसा की सियासत में उठी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायकों के बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ विधायकों द्वारा सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का नाम लेते हुए दावा किया गया कि उन्हें भाजपा की ओर से धमकी दी गई थी। इन आरोपों पर विधायक सेतिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई देते हुए कहा कि उन्हें न तो किसी प्रकार की धमकी मिली है और न ही कोई प्रलोभन दिया गया है।

सीएम की तारीफ अकेला नहीं करता, चोरी-चोरी सब जाते हैं : कांग्रेस पार्टी की तरफ से हलका विधायक जरनैल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जरनैल सिंह के तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं। सीएम की तारीफ व कई विधायकों के चोरी-चोरी सीएम से मिलने के बयान के बाद राजनीति में हलचल मच गई है। विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि हरियाणा के सीएम की तारीफ मैं अकेला नहीं करता सभी करते हैं और सभी चोरी-चोरी मिलने जाते हैं। सीएम से काम लेते हैं। काम लेना भी चाहिए। जरनैल सिंह ने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी का न कोई रोल है न ही दबाब।

इधर... कांग्रेस विधायकों के खुल्लम-खुल्ला बयान दे रहे पार्टी में बगावत के संकेत

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में संग्राम तेज हो गया है। 5 वोट क्रॉस हुए, जबकि चार रद्द हुए हैं। भले ही दिग्गज नेता यह कह रहे हैं कि रद्द जानबूझकर किए गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 32 वोट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस डाट की वजह से कांग्रेस के चार वोट रद्द हुए हैं, उसी डाट लगने की वजह से भाजपा का एक वोट रद्द हुआ है। जबकि एक वोट सीक्रेसी लीक की वजह से रद्द किया गया है। इन सबके बीच कांग्रेस में अब चैलेंज विश्वसनीयता और अपनों पर भरोसा का है। जिस प्रकार विधायक खुलकर बोल रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि कांग्रेस में गुटबाजी को और हवा मिलेगी।

भले ही कांग्रेस प्रत्याशी जीत गया, पर चुनौती नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा दोनों खेमों की बढ़ सकती है। क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों पर हुड्डा तो दो पर सैलजा का ठप्पा माना जाता है। ऐसे में हाईकमान मामले में इनसे भी इस मामले में बातचीत कर सकता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भले ही अपनी पहली परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन मार्क्स थोड़े भी इधर-उधर होते तो पहली परीक्षा कठिन हो सकती थी। दूसरी तरफ विधायकों के जिस प्रकार बयान आ रहे हैं, उनके भी सियासत में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विधायक पार्टी और नेताओं को जमकर कोस रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी में चापलूस लोगों की पूछ है। इस चुनाव के बाद जिस प्रकार विधायक खुलकर अपनों के बारे में बोल रहे हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। खेमों में बंटे नेता भी इशारों में ही निशाना साधते रहे हैं। लेकिन विधायकों की बयानबाजी पार्टी में बगावत के संकेत जरूर दे रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपना घर संभालने के लिए नए सिरे से सियासी कसरत करनी पड़ेगी। क्योंकि चुनाव में मामला विश्वसनीयता और भरोसे का था और उसी पर बड़ा बवाल हो गया है।

पार्टी ने क्रॉस वोट करने वाले पांच विधायकों पर कार्यवाही की बात कही है। ऐसे में यदि कार्यवाही होती है तो ये 2028 में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव में भी पार्टी प्रत्याशी से दूरी बना सकते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस के पास 32 विधायक रहेंगे। जिस प्रकार इस चुनाव में कांग्रेस की एक सीट पर एक तरफा सीट को करीबी मुकाबले में ला खड़ा किया गया, उसके अनुसार कांग्रेस के 32 विधायक होने पर दूसरी सीट जीतना मुश्किल दिखाई दे सकती है।

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का दिल्ली में हुआ आयोजन

सीएम बोले- हरियाणा व अफ्रीका की साझेदारी से विकास को मिलेगी गति

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सैनी ने कहा कि वैश्विक सहयोग के नए दौर में हरियाणा अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा न केवल औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, बल्कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य एलाइड सेक्टर में भी अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। इन क्षेत्रों में दोनों मिलकर परस्पर आपसी सहयोग से एक दूसरे का अनुभव और विशेषज्ञता साझा करते हुए विकास में रफ्तार पकड़ेंगे।

सीएम सैनी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट-2026 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका सामरिक साझेदारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय उर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने की, जबकि केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद साझेदारी नाइक ने भी समिट को संबोधित किया। समिट में जापानी कंपनी ने भी हरियाणा में 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है।

सीएम ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात

चंडीगढ़| सीएम नायब सैनी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर फीडबैक दिया गया। सूत्रों का कहना है कि पंजाब के राजनीतिक हालातों के अलावा हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। संभव है कि कांग्रेस के पांच विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने को लेकर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस की ओर से यदि पांच विधायकों पर कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में उप चुनाव की नौबत आ सकती है। हालांकि यह तभी होगा, जब कांग्रेस के विधायक पदों से खुद इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर प्रदेश में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इनकी तारीखों का मार्च के अंत में ऐलान हो सकता है। इसको लेकर पार्टी की तैयारियों का फीडबैक भी पार्टी की ओर से हाईकमान को दिया जाना है।

समिट के दौरान सीएम सैनी से जापानी कंपनी टीडीके के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

आप के भ्रष्टाचार से सभी वर्ग दुखीः चंडीगढ़ सीएम नायब सैनी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए। लहरागागा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सरकार से हर वर्ग दुखी है और राज्य विकास में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर हरियाणा की तर्ज पर कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी। इस जनसभा में राकेश सिंह गिल ने अपने समर्थकों समेत सीएम की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा।

समाधान शिविरों की शिकायतों के निपटान में फतेहाबाद नंबर 1

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा के फतेहाबाद जिले ने समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटान में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने इस उपलब्धि के लिए फतेहाबाद के डीसी डॉ. विवेक भारती और जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना की। प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि फतेहाबाद अन्य जिलों के लिए उदाहरण पेश कर रहा है। प्रशासन की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर वर्ष 2024 की कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। सफलता का श्रेय टीम भावना को देते हुए डीसी डॉ. विवेक भारती ने सभी विभागाध्यक्षों को आगामी कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। कहा कि वर्ष 2025 की सभी लंबित शिकायतों का निपटान आगामी 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाए। जिन शिकायतों को खारिज किया गया है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट कारणों सहित 2 दिन में पेश की जाए। एसएमजीटी पोर्टल, सीपी ग्राम और सीएम विंडो पर दर्ज मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

न्यूज ब्रीफ

जल जीवन मिशन-के लिए केंद्र के साथ एमओयू

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल व सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन-2.0 के अंतर्गत राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आज हुआ यह एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में राज्य सरकार का ध्यान केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी केंद्रित होगा। इन सभी योजनाओं पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

प्रदेश में 60-70% फसल तबाहः ढांडा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी से किसानों की तबाह हुई फसलों को लेकर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानीपत, करनाल, रोहतक, सोनीपत समेत कई जिलों में गेहूं और सरसों की 60-70 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो व्यापक गिरदावरी शुरू की है और न ही मुआवजे की घोषणा की है। ढांडा ने कहा कि खेतों और मंडियों में पानी भरने से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

फसल खराबे का मुआवजा दे सरकारः कांग्रेस

नारनौल (राजधानी चौपाल) | कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि ने फसलों में काफी अधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रदेशाध्यक्ष ने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से मुलाकात की व फसलों का जायजा लेकर कहा कि सरकार गिरादावरी कराकर फसलों का उचित मुआवजा दे। असमय बारिश ने गेहूं व सरसों की फसल में भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह पसर गईं हैं, इससे दाना काला पड़ने, पैदावार घटने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बढ़ती लागत और महंगाई की मार झेल रहा किसान अब इस प्राकृतिक आपदा के कारण गहरे आर्थिक संकट में डूब गया है। राव नरेंद्र सिंह ने मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी के आदेश जारी करते हुए पारदर्शिता के साथ सर्वे करके मुआवजा दे।

बाल वाटिका के छात्रों को सरकार 1-1 हजार देगी, वर्दी, बस्ता व किताबें खरीद सकेंगे

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | प्रदेश सरकार बाल वाटिका में पढ़ने वाले लगभग एक लाख विद्यार्थियों को एक-एक हजार रुपए देगी। यह राशि हर विद्यार्थी के बैंक खातों में डाली जाएगी। सरकार की ओर से बाल वाटिका में पढ़ने वाले करीब एक लाख विद्यार्थियों को यह राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसमें से वर्दी के लिए 800 रुपए, बस्ता और किताबों के लिए 200 रुपए की राशि होगी। शिक्षा विभाग यह राशि जारी करने की योजना तैयार कर रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के खातों में एक साथ डाले जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। पहली बार यह योजना शुरू की जा रही है। बजट सत्र में इस संदर्भमें सीएम ने ऐलान किया था, अब नए शैक्षणिक सत्र से यह सुविधा विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाएगी। अब भविष्य में भी जो विद्यार्थी बाल वाटिका में एडमिशन लेंगे, उनको भी यह सुविधा मिलती रहेगी।

6 जिलों के अस्पतालों में पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होंगी एमआरआई स्कैन सेवाएं

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा (नूंह) और रेवाड़ी में सीटी स्कैन सेवाओं को हायर करने की स्वीकृति दी गई। मांडीखेड़ा (नूंह), रेवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक और चरखी दादरी के सिविल अस्पतालों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एमआरआई स्कैन सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम व जींद के सिविल अस्पतालों में मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड क्लीनिंग सेवाएं शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

एचकेआरएन कर्मचारियों को नहीं मिली जॉब सिक्योरिटी, सीएम को लिखा पत्र

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | एचकेआरएन कर्मचारियों को दी जाने वाली जॉब सिक्योरिटी का समय लगातार बढ़ाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने इसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि एचओडी स्तर पर काम बाकी है। इसलिए सरकार एचओडी का निर्देश देकर प्रक्रिया पूरी कराए, ताकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल सके। अभी तक एक भी कर्मचारी को वह जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। संघ प्रदेशाध्यक्ष जसविंद्र दूहन का कहना है कि राज्य के विभिन्न विभागों में 1,20 लाख अनुबंधित कर्मचारियो को जॉब सिक्योरिटी का लाभमिलना है। बिजली विभाग के सभी अनुबंधित कर्मचारियों ने अपना डेटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड कर दिया था। डीडीओ स्तर पर भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है : बड़ौली

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं और उनके समर्पण से ही संगठन मजबूत बनता है। सोनीपत के मुरथल मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त, अनुशासित और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से कार्य करते हैं। प्रशिक्षण को सतत प्रक्रिया बताते हुए बड़ौली ने कार्यकर्ताओं से अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाने और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का आह्वान किया।

अब स्कूलों की मरम्मत खुद करा सकेंगे मुखिया

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब मरम्मत आदि के कार्य मुखिया अपने स्तर पर ही करा सकेंगे। साल में पांच लाख रुपए तक खर्चने की इजाजत होगी। स्कूल मुखिया को साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, दीवारों की मरम्मत, तारबंदी आदि कराने की इजाजत होगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों में ऐसी कमियों को तुरंत ठीक कराया जाए। मरम्मत कार्यों का खर्च चाइल्ड वेलफेयर फंड से नियमों के अनुसार किया जाए। इस तरह के कार्यों के लिए मुख्यालय में प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है। यदि चाइल्ड वेलफेयर फंड में पर्याप्त राशि नहीं है तो स्कूल संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के जरिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद यह कार्य स्कूल स्तर पर गठित लोकल परचेज कमेटी के माध्यम से कोटेशन लेकर किया जाएगा।

पटवारियों को मिलेंगे 4156 टैबलेट, फील्ड सर्वे कर दर्ज कर सकेंगे डेटा

सभी जानकारी सीधे रियल टाइम में केंद्रीय सर्वरों पर अपलोड कर सकेंगे

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| सरकार ने राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत करते हुए राज्य भर में पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी है। यह पहल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल द्वारा मंजूर की गई है। इसका उद्देश्य फील्ड संचालन का आधुनिकीकरण करना, प्रक्रियागत देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार लाना है। वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत तकनीक को कार्यालयों और शहरी केंद्रों से आगे बढ़ाकर फील्ड स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जहां अधिकारी सीधे नागरिकों से संपर्क करते हैं।

वॉइस-टू-टेक्स्ट से मिलेगी सुविधा

वॉइस-टू-टेक्स्ट से डेटा एंट्री को सरल बनाने में सुविधा होगी। इससे मेहनत कम होगी और सटीकता बढ़ेगी। इन टैबलेट में उच्च स्तर के फीचर्स होंगे, जिनमें बड़ा डिस्प्ले, उन्नत प्रोसेसिंग क्षमता, पर्याप्त स्टोरेज और पूरे दिन के फील्ड कार्य के लिए लंबी बैटरी लाइफ शामिल हैं।

5 जी और एलटीई कनेक्टिविटी के साथ-साथ जीपीएस और इमेजिंग सुविधाएं इन्हें दूरदराज और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने योग्य बनाती हैं। सभी 4,156 टैबलेट को दो साल के क्लाउड-होस्टेड लाइसेंस के साथ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम फील्ड स्टाफ और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी होगा। दशकों से पटवारी व कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बने नक्शों और व्यापक कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से कठिन रही है। इन टैबलेट के आने से अब अधिकारी फील्ड सर्वे कर सकेंगे, डेटा दर्ज कर सकेंगे, जीपीएस-टैग्ड तस्वीरें ले सकेंगे और जानकारी को सीधे रियल टाइम में केंद्रीय सर्वरों पर अपलोड कर सकेंगे।

नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की प्रक्रिया शुरू; करनाल व कुरुक्षेत्र के बीच में बनेगा, सरकार ने मांगी अनुमति

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह हवाई अड्डा करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में बनाने की योजना है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है, ताकि हवाई अड्डा बनाने की अनुमति मिल सके।

बड़ी बात ये है कि हवाई अड्डे से दो ऐतिहासिक शहर जुड़ जाएंगे। कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और करनाल बासमती चावल का हब है, कई अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं। सरकार का मानना है कि नए हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में तैयार किया जा सकेगा। क्योंकि करनाल से दिल्ली की दूरी करीब 125 किलोमीटर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के दौरान इसका ऐलान किया था, अब इसके लिए अनुमति ली जा रही है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के अनुसार प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं।

बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हिसार में एयरपोर्ट पहले ही शुरू हो चुका है। करनाल में भी नया हवाई अड्डा बनाया जाए, इससे प्रदेश के लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे।

क्षेत्रीय विकास पर भी पड़ेगा प्रभावः एयरपोर्ट के निर्माण से करनाल, कुरुक्षेत्र और आस-पास के जिलों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे उद्योग, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं। क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। करनाल में पहले से मौजूद नागरिक विमानन क्लब का भी विस्तार किया जा रहा है।

नए हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रफल करीब 600 एकड़ पहला चरण निर्धारित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में सुविधा विकसित करना और हरियाणा में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। परियोजना से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिक मंजूरियां वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

अबकी बार से सरकारी स्कूलों में फ्रेंच-जर्मन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी

60 शिक्षकों को जर्मन भाषा में प्रशिक्षित किया जाएगा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दो विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। इनमें एक भाषा फ्रेंच व दूसरी जर्मन होगी। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में जर्मन भाषा के प्रोत्साहन हेतु जर्मन दूतावास/गोएथे इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें बहुभाषिकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को विशेष महत्व दिया गया है। विभाग द्वारा पहले से ही फ्रेंच भाषा कार्यक्रम प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी क्रम में अब जर्मन भाषा को भी प्रदेश के चयनित सरकारी विद्यालयों विशेष रूप से संस्कृत मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता शिक्षा विद्यालय तथा पीएम श्री स्कूलों में लागू किया जाएगा। विभाग शीघ्र ही ईओआई जारी करेगा, इसके माध्यम से लगभग 60 शिक्षकों का चयन कर उन्हें जर्मन भाषा में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक आगे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भाषा शिक्षा प्रदान करेंगे। एमओयू के तहत जर्मनी एवं भारत के बीच भाषा, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, इससे अंतरराष्ट्रीय अनुभव एवं समझ विकसित होगी।

नव सृष्टि का संदेश और नवरात्र का आध्यात्मिक विज्ञान

नैसर्गिक पवित्रता का आवाहन

नवरात्र का पर्व वास्तव में नैसर्गिक पवित्रता और बाल-स्वभाव के आवाहन का पर्व है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि जगदंबा की प्रसन्नता भव्य आयोजनों या शोर-शराबे में नहीं, बल्कि मन की सरलता में निहित है। यह आवाहन जितना सुरुचिपूर्ण, सादगी भरा और प्रकृति के साथ संतुलन रखते हुए किया जाए, उतना ही फलदायी होता है। जब हम एक अबोध बालक की तरह निष्छल मन से माँ को पुकारते हैं, तभी वह आदिशक्ति हमारे भीतर जाग्रत होती है। नवरात्र का वास्तविक संदेश 'नव सृष्टि' का निर्माण है—एक ऐसी सृष्टि जो आंतरिक शांति और बाहरी संतुलन पर आधारित हो।

खगोलीय घटना और संपात का रहस्य

वर्ष के चक्र में दो मुख्य नवरात्र आते हैं—शारदीय और वासंती। ये दोनों ही समय प्रकृति में 'संपात' की स्थिति के गवाह होते हैं। स्थूल रूप में संपात का अर्थ है दिन और रात का बराबर होना, जहाँ पृथ्वी सूर्य से एक सम-दूरी पर स्थित होती है। लेकिन सूक्ष्म रूप से इसका अभिप्राय जीवन में 'संतुलन' प्राप्त करने की स्थिति से है। यह वह संधि काल है जहाँ ताप और शीत के बीच एक सामंजस्य स्थापित होता है। इसी संतुलन की स्थिति में साधना सबसे अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं एक शांत और स्थिर अवस्था में होती है।

अहंकार का त्याग और आदिशक्ति का स्रोत

नवरात्र में जगदंबा की विशेष पूजा का विधान इसलिए किया गया है ताकि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और उपलब्धियों के अभिमान को त्यागने का अभ्यास कर सके। हमें यह समझना होगा कि संसार की समस्त ऊर्जा का स्रोत केवल एक ही है—वह 'आदिशक्ति' है। वही माँ है जो अनंत रूपों में इस दृश्य जगत में व्यक्त होती है और कार्य पूर्ण होने पर पुनः अदृश्य, अव्यक्त करुणा और ममता के प्रवाह में समा जाती है। हमारी सत्ता उस महाशक्ति के सामने एक बूंद के समान है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है।

शक्ति के प्राकट्य के दो दिव्य कारण

माँ भगवती के व्यक्त होने के पीछे दो मुख्य कारण माने गए हैं। पहला तब, जब सृष्टि में आसुरी शक्तियों का मद बढ़ जाता है और न्याय व्यवस्था डगमगाने लगती है। जब दुर्बल व्यक्ति केवल शोषण का पात्र बन जाता है, तब माँ 'काली' के रूप में अवतरित होती हैं। वह शक्ति के मद का मर्दन करती हैं और अधर्म का विनाश करती हैं। उनका यह रूप विकराल जरूर है, लेकिन यह पापियों के लिए भय और भक्तों के लिए अभय का प्रतीक है। दूसरा कारण उनकी दिव्य लीला है। वह एक छोटी सी बच्ची बन जाती हैं, जो अपने बच्चों की पुकार पर उन्हें खिलौने देने वाली ममतामयी माँ का रूप धर लेती हैं।

शक्ति, संयम और पात्र की स्वच्छता

आदिशक्ति 'भुवनमोहिनी' भी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी सुंदरता से सम्मोहित करती है। प्रकृति में सौंदर्य तभी निखरता है जब वह 'सु' अर्थात अच्छी तरह समता या संतुलन प्राप्त करती है। यह संतुलन लेने और देने वाले के बीच, आवेग और शांति के बीच होना अनिवार्य है। नवरात्र के व्रत का मूल उद्देश्य अपनी आंतरिक शक्ति को संयम और नियमों के माध्यम से सुरक्षित करना है। शक्ति का अनावश्यक अपव्यय रोकना ही साधना है। पूरी सृष्टि से जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसे अपने भीतर धारण करने के लिए साधक के 'पात्र' (शरीर और मन) का स्वच्छ होना अनिवार्य है।

पंचतत्वों का अर्पण: सब कुछ तुम्हारा है माँ

हम पूजा में जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गंध के रूप में हम पृथ्वी तत्व को अर्पित करते हैं।

पुष्प के रूप में हम खिले हुए और प्रसन्न 'आकाश' को समर्पित करते हैं। धूप के रूप में सर्वशोधक 'वायु' तत्व और दीप के रूप में 'अग्नि' तत्व माँ को भेंट किया जाता है। अंत में, नैवेद्य के रूप में जल का अमृत अर्पित होता है। इन पांचों तत्वों का समावेश 'तांबूल' (पान) में होता है। यह संपूर्ण अर्पण इस भाव से है कि 'हे माँ, इस सीमित शरीर में जो तत्व हैं, वे आपके इस असीम ब्रह्मांड के ही अंश हैं, अतः इन्हें आप ही को सौंपता हूँ।'

ममता का न्याय और अद्वैत भाव

माँ हमेशा जागती रहती है, वह हर बच्चे की सूक्ष्मता से देखरेख करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि कोई बच्चा दूसरे के साथ अन्याय न करे। जो बच्चा दूसरों को सताता है, माँ उसे दंड देती है और जो चोट खाया हुआ है, उसे अपनी ममता से सहलाती है। यही कारण है कि वह सताने वाले को डरावनी और सताए जाने वाले को दयालु लगती है, जबकि तत्वतः वह एक ही है। उसके अनेक रूपों में कोई वास्तविक भेद नहीं है; वह अद्वैत है। जिस प्रकार व्यापार में वस्तुएं अलग दिखती हैं पर तत्व एक ही होता है, वैसे ही माँ की विविध शक्तियां एक ही परम चेतना का विस्तार हैं।

सरलता और निश्छलता का मार्ग

जगदंबा की वत्सल छाया सबके लिए समान है। चाहे वह महान ज्ञानी हो, तपस्वी हो या निपट अज्ञानी और सांसारिक विषयों में फंसा हुआ मनुष्य। माँ के सामने पहुंचते ही सब कुछ विस्मृत हो जाता है, बस एक ही सत्य शेष रहता है—'संतान कैसी भी हो, माँ तो बस माँ होती है।' एक बार अपनी सारी चालाकियों और दुराव-छिपाव को छोड़कर, अपनी समस्त दुर्बलताओं और क्षमताओं को माँ के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम स्वयं को पूरी तरह उन पर छोड़ देते हैं, तभी वास्तविक सुरक्षा का अनुभव होता है।

वर्तमान की विसंगतियां और अमंगल का घेरा

आज के समय में माँ की जो अर्चना हो रही है, उसमें वह भाव और सौष्ठव कम होता जा रहा है जो अनिवार्य था। आज उत्सवों में उत्साह और भावोन्माद तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे अक्सर दूसरे से श्रेष्ठ दिखने का अहंकार छिपा होता है।

जगदंबा इस दिखावे को स्वीकार नहीं करतीं और जब साधना में प्रदर्शन आ जाता है, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज हम जिस अमंगल और अशांति से घिरे हैं, उसका कारण हमारी दिखावटी और खोखली पूजा पद्धतियां ही हैं।

विश्व-मंगल का नया अध्याय

यदि हम नवरात्र के वास्तविक संदेश को समझ लें, तो हमारा आवाहन शोर-शराबे वाली कर्ण-कटु ध्वनियों का हाहाकार नहीं होगा। हमारे आयोजन दिखावटी होने के बजाय आंतरिक शांति के केंद्र बनेंगे। नवरात्र का संदेश 'नव सृष्टि' का संदेश है—एक ऐसी नई शुरुआत जहाँ सादगी, प्रकृति के प्रति सम्मान और बाल-सुलभ निश्छलता सर्वोपरि हो। यदि हम इस मर्म को हृदयंगम कर लें, तो न केवल हमारे जीवन में बल्कि संपूर्ण विश्व-मंगल का एक नया और स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो सकता है।

शक्ति की उपासना प्रदर्शन नहीं, अंतर्मन की शुद्धि है।

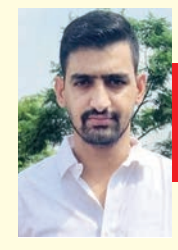

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

चैत्र नवरात्रि 2026

पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, हाथी पर होगी विदाई...

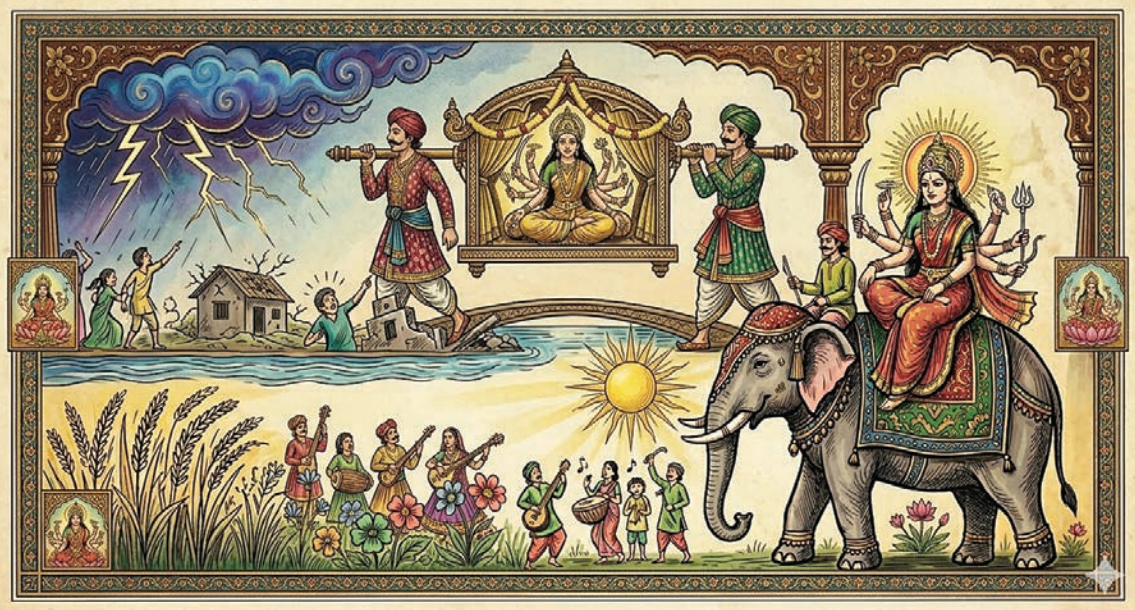

भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में शक्ति उपासना का महापर्व 'चैत्र नवरात्रि' इस वर्ष विशेष ज्योतिषीय संयोगों के साथ आ रहा है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च, बृहस्पतिवार से होने जा रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार, नवरात्रि के प्रारंभ और समापन के दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन्हीं दिनों के आधार पर जगत जननी मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के 'वाहन' तय होते हैं। इस वर्ष माता का आगमन 'पालकी' पर हो रहा है, जबकि उनकी विदाई 'हाथी' पर होगी, जो आने वाले समय के लिए मिश्रित संकेत दे रहे हैं।

पालकी पर आगमनः सावधानी और सतर्कता का संकेत

शास्त्रों के अनुसार, यदि नवरात्रि का प्रारंभ बृहस्पतिवार या शुक्रवार को होता है, तो मां दुर्गा 'पालकी' (डोली) पर सवार होकर आती हैं। इस वर्ष 19 मार्च को गुरुवार होने के कारण माता का वाहन पालकी ही रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में देवी का पालकी पर आना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पालकी पर आगमन महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता, दंगे और जन-हानि जैसी विषम परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। यह कालखंड समाज के लिए धैर्य और विशेष सावधानी बरतने वाला हो सकता है, जहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजग रहना अनिवार्य होगा।

विभिन्न वारों के अनुसार आगमन के फल

देवी भागवत के गूढ़ रहस्यों के अनुसार, माता के आगमन का वाहन पूरी तरह से 'वार' (दिन) पर निर्भर करता है। यदि नवरात्रि रविवार या सोमवार को शुरू हो, तो माता हाथी पर आती हैं, जो अत्यधिक वर्षा और समृद्धि का प्रतीक है।

शनिवार या मंगलवार को प्रारंभ होने पर माता का वाहन 'घोड़ा' होता है, जो सत्ता परिवर्तन, युद्ध और विपक्ष के लिए लाभकारी किंतु सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल माना जाता है। वहीं, बुधवार को आगमन होने पर मां 'नाव' पर सवार होती हैं, जो भरपूर फसल और मनोकामना पूर्ति का शुभ संकेत है। इस वर्ष पालकी पर आगमन होने के कारण विद्वान इसे चुनौतियों से भरा समय मान रहे हैं।

हाथी पर प्रस्थानः सुख-समृद्धि और ज्ञान का उदय

यद्यपि आगमन के संकेत चिंताजनक हैं, किंतु माता का प्रस्थान (विदाई) अत्यंत शुभकारी होने वाला है। इस वर्ष नवरात्रि का समापन 27 मार्च को हो रहा है।

बुधवार या शुक्रवार को जब माता विदा होती हैं, तो उनका वाहन 'हाथी' होता है। हाथी पर माता की विदाई को सुख, शांति और समृद्धि का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। यह अच्छी वर्षा, कृषि में लाभ, आर्थिक उन्नति और समाज में ज्ञान की वृद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभिक चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद, अंततः देश और जनमानस में खुशहाली और संपन्नता का वास होगा।

विदाई के वाहनों का प्रभाव

माता की विदाई के वाहनों का प्रभाव भी देश की स्थिति को प्रभावित करता है। यदि विदाई रविवार या सोमवार को हो, तो सवारी 'भैंसा' होती है, जो शोककारक मानी जाती है। शनिवार या मंगलवार को विदाई होने पर 'मुर्गा' वाहन होता है, जिससे दुखों में वृद्धि होती है।

वहीं, बृहस्पतिवार को विदाई होने पर माता 'मनुष्य' की सवारी करती हैं, जो देश में चारों ओर सुख-शांति का संचार करता है। इस वर्ष शुक्रवार को 'हाथी' पर प्रस्थान होना यह दर्शाता है कि भक्तों को उनके अच्छे कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होगा और राजकीय स्तर पर भी उन्नति देखने को मिलेगी।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा

भारतीय नव वर्ष का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विमर्श

भारतीय काल-गणना के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब उत्तर भारत का नया साल अपनी पूरी भव्यता के साथ दस्तक देता है। इस दिन पंचांग के पन्ने पलटते हैं, नए वर्ष के 'राजा' और 'मंत्री' का चुनाव होता है, और कृषि के आधार पर 'धान्य' व 'मेघ' के अधिपति तय किए जाते हैं। श्रद्धालु समाज अपने भविष्य का फल जानने के लिए ज्योतिषियों की शरण में जाता है। धार्मिक परिवेश में लोग तेल-उबटन लगाकर आत्मिक शुद्धि करते हैं और महाराज विक्रमादित्य के गौरवशाली नाम से जुड़े 'संवत्सर' का स्वागत करते हैं...

सांस्कृतिक समन्वय की अनूठी दास्तान

आचार्य द्विवेदी रेखांकित करते हैं कि उत्तर भारत के नव वर्ष की परंपरा वास्तव में नाना प्रकार के विश्वासों और संस्कृतियों के अद्भुत मेल का परिणाम है। प्राचीन भारत में शकों, यवनों (यूनानियों) और आर्यों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष हुए, लेकिन सांस्कृतिक धरातल पर ये सभी धाराएं एक-दूसरे में विलीन होती चली गईं। राजनीति के कठोर आवरण के भीतर विश्वासों का यह समन्वय एक चमत्कार की तरह है। हमारा नया साल हर बार यह संदेश लेकर आता है कि स्वार्थों और विचारधाराओं के संघर्ष क्षणिक होते हैं; उनके भीतर मनुष्य अनजाने में ही एकता और मिलन की भूमिका तैयार कर लेता है।

सृष्टि का आरंभ-ज्योतिषीय आधार

ज्योतिष की प्राचीन पोथियों में यह दृढ़ विश्वास मिलता है कि जब विधाता ने सृष्टि का चक्र प्रथम बार प्रवर्तित किया, तो वह दिन 'चैत्र शुदि (शुक्ल पक्ष) रविवार' का था। ब्रह्मगुप्त (7वीं शताब्दी) और भास्कराचार्य (12वीं शताब्दी) जैसे महान गणितज्ञों और ज्योतिषियों के ग्रंथों में इस तिथि की विस्तृत चर्चा मिलती है। ब्रह्मगुप्त के कार्यों का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके ग्रंथों के अरबी अनुवाद ने पश्चिमी जगत को काल-गणना के नए सिद्धांतों से परिचित कराया। यह ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित करता है कि कम-से-कम डेढ़ हजार वर्षों से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही वर्षारंभ की तिथि माना जाता रहा है। रविवार को सृष्टि के प्रारंभ से जोड़ना सूर्य की प्रधानता को दर्शाता है, जिसे भारतीय मनीषा में 'जगत की आत्मा' कहा गया है।

'वार' प्रथा का रोचक इतिहास

एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सात वारों (रविवार, सोमवार आदि) की यह प्रथा भारत में कितनी पुरानी है? ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं मानी जाती। इसका सबसे पुराना शिलालेखीय साक्ष्य कच्छ के 'अंधी गाँव' से प्राप्त हुआ है, जो शक क्षत्रप रुद्रदामन के समय का (130 ईस्वी) है। इसमें स्पष्ट रूप से 'गुरुवार' शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार, राजा हाल की 'गाथा सप्तशती' में भी 'अंगारक' (मंगलवार) का वर्णन है। अतः यह स्पष्ट है कि विधाता द्वारा रविवार को सृष्टि शुरू करने का जो धार्मिक विश्वास है, वह ईस्वी सन् की प्रारंभिक शताब्दियों के आसपास ही विकसित हुआ होगा। यह दर्शाता है कि कैसे धार्मिक आस्थाएं ऐतिहासिक विकासक्रम के साथ खुद को ढालती रही हैं।

राजा-मंत्री का खगोलीय मंत्रिमंडल

भारतीय ज्योतिष में नव वर्ष के प्रशासन की एक बड़ी ही रोचक व्यवस्था है। 'ज्योतिष फलोदय' जैसे ग्रंथों के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार होता है, वही ग्रह उस पूरे वर्ष का 'राजा' कहलाता है। वहीं, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है (मेष संक्रांति), उस दिन का वार अधिपति 'मंत्री' का पद संभालता है। प्राचीन काल से ही भारत में नौ ग्रह (सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु) मान्य रहे हैं। हालांकि वार केवल सात ग्रहों के नाम पर हैं, राहु और केतु इस व्यवस्था से बाहर रहते हैं। यह व्यवस्था प्रकृति और नक्षत्रों के साथ मानव जीवन के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है।

वैश्विक समानता-रविवार का महत्व

यह एक अद्भुत शुभ संवाद है कि चाहे ईसाई हों, यहूदी हों या हिंदू, सभी ने सात दिनों के चक्र को स्वीकार किया है। ईसाईयों ने स्वयं को यहूदियों से अलग दिखाने के लिए रविवार को सप्ताह का आदि-दिन घोषित किया। भारत में भी सूर्य की उपासना के कारण रविवार को विशेष महत्व दिया गया। द्विवेदी जी कहते हैं कि परस्पर विरोधी समझी जाने वाली संस्कृतियां भी समय के अंतराल में विचित्र भाव से एक हो जाती हैं। हमारा नया साल हमें इन सूक्ष्म कड़ियों को पहचानने और वैश्विक एकता के भाव को समझने के लिए मजबूर करता है।

विक्रम और शक संवत् का संगम

विक्रम संवत्, जिसे प्राचीन काल में 'मालव संवत्' कहा जाता था, संपूर्ण भारत में एक ही तिथि से शुरू नहीं होता। मालवा और दक्षिण भारत में यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (दीपावली) से आरंभ होता है। उत्तर भारत में इसके चैत्र से शुरू होने का मुख्य कारण 'शक संवत्' का प्रभाव है। शक राजाओं ने चैत्रादि गणना का प्रवर्तन किया था, जो भारतीय फसलों और ऋतुचक्र के अधिक अनुकूल था। बाद में, व्यावहारिक सुगमता के लिए उत्तर भारत के पंचांगकारों ने दोनों संवतों का आरंभ एक ही तिथि (चैत्र प्रतिपदा) से मानना शुरू कर दिया। गुप्त वंश के राजाओं और बाद के मुस्लिम शासकों ने भी इसी के आसपास नए संवत् चलाए, क्योंकि वसंत ऋतु का यह समय आर्थिक और प्राकृतिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त था।

वसंत का व्यावहारिक संदेश

अंततः, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह पर्व हमें केवल तिथियों के फेर में नहीं उलझाता, बल्कि यह 'वसंतादि संवत्' की व्यावहारिकता की घोषणा करता है। जब प्रकृति पल्लवित होती है और फसलें कटने को तैयार होती हैं, तब नया वर्ष मनाना जीवन की जीवंतता का प्रतीक है। पुराने भारतवासी व्रत और उपवास के माध्यम से इस परिवर्तन को स्वीकार करते थे। यह नया वर्ष हमें सिखाता है कि समय केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, आस्था और सामाजिक समन्वय का जीवित दस्तावेज है। यह हमें संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक विशाल मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है।

लेखक : राहुल हिंदुस्तानी

लेबनान के दक्षिणी हिस्से की ओर गोले दागे...

इजराइल की एक सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर तोप ने शुक्रवार को लेबनान के दक्षिणी हिस्से की ओर गोले दागे।

दक्षिणी लेबनान के कफर तेबनित पर इजराइली हवाई हमला

दक्षिणी लेबनान के नबातियेह जिले के कफर तेबनित शहर पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। हमले के बाद इलाके में धमाके और नुकसान की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक लेबनान में इजराइली हमलों में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

अराद हमले के बाद 150 परिवारों को हटाया गया

इजराइल के दक्षिणी शहर अराद के मेयर ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद प्रभावित इलाके से करीब 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इजराइल की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, इस हमले में कम से कम 64 लोग घायल हुए हैं।

इजराइल में स्कूल बंद, सभी ऑफलाइन क्लासेस कैंसिल

इजराइल के शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में रविवार और सोमवार के लिए सभी ऑफलाइन (इन-पर्सन) कक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह फैसला हाल के मिसाइल हमलों के बाद लिया गया है, जिनमें अराद और डिमोना शहरों में करीब 100 लोग घायल हुए हैं।

ट्रम्प का ईरान को अल्टीमेटम- 48 घंटे में होर्मुज खोलें नहीं तो पावर प्लांट तबाह करेंगे

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होनें कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को लिखा, 'अगर ईरान 48 घंटे के भीतर होर्मुज को नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी।' वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के खातम अल-अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाघारी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट (डिसेलिनेशन प्लांट) और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेगा।

ईरान का इजराइली शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला

ईरान ने शनिवार रात इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डिमोना वही शहर है जहां इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूज पजशकियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि BRICS को ईरान पर हो रहे हमले रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि BRICS को बिना किसी दबाव के, अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल कम होगा।

ईरान बोला- अमेरिका-इजराइल के वाटर प्लांट उड़ा देंगे

ईरानी नेवी ने भारतीय जहाज होर्मुज पार कराया : दावा- हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। ईरानी नेवी ने 13 मार्च की रात को एक भारतीय जहाज को सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कराया था। LPG लेकर आ रहा ये जहाज 10 दिन से फारस की खाड़ी में फंसा था। यह खबर ब्लूमबर्ग ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह काम भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद हुआ। जहाज को पहले से तय रास्ते से निकाला गया ताकि वह हमलों से बच सके। इस दौरान जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया था। हालांकि रिपोर्ट में इस जहाज का नाम नहीं बताया गया है। अभी तक दो भारतीय जहाज शिवालिक (16 मार्च) और नंदा देवी (17 मार्च) होर्मुज के रास्ते LPG लेकर भारत पहुंचे हैं। वहीं फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के अहम शिपिंग रूट्स में शामिल है। यहां से दुनिया भर की करीब 20% ऑयल की सप्लाई होती है।

ईरान बोला- इजाजत लेकर होर्मुज से गुजर सकते हैं विदेशी जहाज

ईरान ने कहा है कि विदेशी जहाज उसकी अनुमति के साथ होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। यह बात अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कही। ब्रिटेन में ईरान के राजदूत अली मौसवी, ने मेहर न्यूज एजेंसी से कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के साथ-साथ ईरान की संप्रभुता और अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और नाविकों की सुरक्षा के लिए IMO और अन्य देशों के साथ सहयोग करने को तैयार है। मौसवी ने यह भी साफ किया कि होर्मुज सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। उन्होंने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और इजराइल के युद्ध को जिम्मेदार बताया।

देश लगातार हमले झेल रहा, ऐसे में शांत रहने की उम्मीद बेकार

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि जब देश लगातार घातक हवाई हमलों का सामना कर रहा है, तो उससे संयम बरतने की उम्मीद करना बेकार है। स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिन हमलावरों ने यह संघर्ष शुरू किया है, उन्हें पहले अपने हमले रोकने चाहिए। इसके बाद ही तेहरान की तरफ से किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है।

कमजोर हो चुका ईरान युद्ध लंबा क्यों खींच रहा : सरेंडर से इनकार, जंग को महंगा बनाकर दुश्मन को झुकाने की कोशिश में जुटा

तेहरान/तेल अवीव/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य कमांड ढांचे के अहम लोग मारे गए हैं। इससे उसकी नेतृत्व व्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। ईरान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी, बुनियादी ढांचे के नुकसान और सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान की बची हुई लीडरशिप लगातार आक्रामक बयान दे रही है। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। उन्हें और नेताओं के मारे जाने की परवाह नहीं है और वे इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार हैं, चाहे इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर क्यों न पड़े।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का मकसद इस युद्ध में जीत हासिल करना नहीं है। उसका असली मकसद है अपने अस्तित्व को बचाना, दुश्मनों को डराना और ऐसी स्थिति बनाना जिसमें वह युद्ध के बाद की शर्तें तय कर सके। वह संघर्ष बढ़ा रहा है ताकि बाकी देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा हो जाए और वे समझौता करने पर मजबूर हो जाएं।

जंग खत्म करने के लिए हर्जाना चाहता है ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान से सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। वह कह रहा है कि वह इस संघर्ष में टिके रहने में सफल रहा है और अब शांति के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्र में नई व्यवस्था बनाई जाए। वह युद्ध के नुकसान की भरपाई (मुआवजा) भी मांग रहा है और खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में बदलाव चाहता है।

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि युद्धविराम तभी संभव है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर युद्धविराम से दुश्मन को अपनी ताकत फिर से तैयार करने का मौका मिलता है, जैसे रडार ठीक करना या मिसाइल सिस्टम मजबूत करना तो ऐसा युद्धविराम बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा, जब तक दुश्मन अपने हमले पर पछतावा न करे और दुनिया और क्षेत्र में सही राजनीतिक और सुरक्षा हालात न बन जाएं।

ईरानी विदेश मंत्री बोले- होर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम बने

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें ईरान के हितों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कुछ खास शर्तों के तहत ही होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आगे चलकर अपने विदेशों में फंसे पैसे को छुड़ाने की मांग कर सकता है या इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों से टैक्स भी ले सकता है। गालिबाफ ने साफ कहा कि होर्मुज की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब 'युद्ध के बाद क्या होगा' इस सवाल पर भी दबाव बढ़ रहा है। दो दशकों तक पश्चिमी देशों और ईरान के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई और देश की सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने तेज और लगातार हमले किए। उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इससे खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते और खराब हो गए और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी असर पड़ा। खासकर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के कारण।

'इजराइल के और करीब आ सकते हैं खाड़ी देश'

हालांकि यह साफ नहीं है कि ईरान की यह रणनीति सफल होगी या नहीं। अब तक ज्यादातर खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि उन पर हमले हुए हैं। ऐसे में कई देशों ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करेंगे। UAE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN से कहा कि खाड़ी देशों में ईरान को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और यह सोच आने वाले कई दशकों तक नहीं बदलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि UAE होर्मुज को खोलने के लिए किसी गठबंधन में शामिल हो सकता है। उनका मानना है कि ईरान की रणनीति गलतफहमी पर आधारित है और युद्ध के बाद खाड़ी देश इजराइल के और करीब आ सकते हैं। UAE की एक मंत्री ने कहा कि उनके देश पर हमला होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता लंबे समय से बना हुआ है और यह भरोसे पर टिका है, जो संकट के समय भी नहीं टूटेगा।

दबाव को अपने फायदे में बदलना चाहता है ईरान

मिडिल ईस्ट से जुड़े मामलों की एक्सपर्ट सिना तूस्सी ने CNN से कहा कि ईरान चाहता है कि अभी जो दबाव है, उसे बाद में अपने फायदे में बदल सके। वह ऐसी स्थिति चाहता है जहां उसे अलग-थलग या खत्म करने की कोशिश न हो, बल्कि उसे क्षेत्र की स्थिरता का जरूरी हिस्सा माना जाए।

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को कहा कि ईरान युद्ध हार रहा है। ट्रम्प ने भी कहा कि ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसके नेता लगभग हर स्तर पर खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान फिर कभी अमेरिका, उसके सहयोगियों या दुनिया को धमकी न दे सके। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने 61वीं बार हमला किया, जिसमें इजराइल में एक दंपति की मौत हो गई।

ईरान जीत नहीं रहा, उसे जीतने की जरूरत भी नहीं

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नारगिस बाजोगली का कहना है कि पारंपरिक युद्ध के हिसाब से ईरान जीत नहीं रहा है, लेकिन उसे उसी तरह जीतने की जरूरत भी नहीं है। उसकी रणनीति अलग है। ईरान एक अलग रणनीति अपना रहा है, जिसमें वह युद्ध को इतना महंगा बना देना चाहता है कि सामने वाला देश उसे जारी न रख सके। उनका कहना है कि अमेरिका और खाड़ी देश लंबे समय तक तेल व्यापार में रुकावट और बढ़ती कीमतों को सहन नहीं कर सकते। किसी समय वे कहेंगे कि अब बहुत हो गया और यही दबाव ईरान बनाना चाहता है। ईरान ने पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने ऐसे प्लान बनाए थे कि बड़े हमले होने पर छोटे-छोटे यूनिट्स अलग-अलग जगहों से काम कर सकें।

अमेरिका सहयोगी देशों पर दबाव बना रहा

जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट फिलिप्स ओ'ब्रायन का कहना है कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि थोड़े समय में दबाव डालकर ईरानी सरकार को झुका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्सर देश जब युद्ध शुरू करते हैं, तो यह मान लेते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा और उनकी सेना जल्दी अपना टारगेट हासिल कर लेगी। लेकिन असल में हालात उतने आसान नहीं होते। ओ'ब्रायन के मुताबिक, ट्रम्प को लगा था कि कुछ दिनों तक बमबारी करने के बाद ईरान में नई सरकार बन जाएगी और अमेरिका जीत का ऐलान कर देगा। लेकिन अब तीन हफ्ते बीत चुके हैं और युद्ध अभी भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब अमेरिका खुद तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या करना है। वह एक तरफ लड़ाई बढ़ाने पर सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर कुछ पाबंदियां भी कम कर रहा है। साथ ही, अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे खाड़ी क्षेत्र में उसकी मदद करें और उसके लिए काम करें।

जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की

विदेश मंत्री जयशंकर ने आज ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघच से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के आपसी रिश्तों और आगे के सहयोग को लेकर भी बात की गई। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमले गलत हैं और इन्हें रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे स्वतंत्र देशों को मिलकर उन देशों पर दबाव बनाना चाहिए जो युद्ध शुरू करने के जिम्मेदार हैं, ताकि ये हमले बंद हो सकें और दोबारा न हों। उन्होंने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि यहां जो तनाव है, वह इन हमलों का ही नतीजा है। उनका कहना है कि हालात तभी सामान्य होंगे जब हमले पूरी तरह बंद होंगे और भविष्य में ऐसे हमले दोबारा न हों, इसकी गारंटी दी जाए। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी है। भारत और ईरान के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाएगा।

ईरान में अब तक 20,984 लोग घायल

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में अब तक 20,984 लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 7 अस्पतालों को खाली कराना पड़ा है, क्योंकि वहां काम करना सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा, 36 एम्बुलेंस भी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि उनका देश डोनाल्ड ट्रम्प के सबस सिखाएगा।

सोशल मीडिया पर आए दिन तेजी से वजन कम करने वाली खबरें छाई रहती हैं। पर, क्या यह सुरक्षित है? तेजी से वजन कम करना मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्र को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या ध्यान रखें, बता रहे हैं...

चिंता बढ़ा सकता है तेजी से वजन घटाना

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में बढ़ते मोटापे के प्रति चिंता जाहिर की है। यह चिंता अकारण नहीं है। हालिया अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक देश में 45 करोड़ वयस्क अधिक वजन या मोटापे से जूझ रहे होंगे। 15 से 24 आयु वर्ग में मोटापे से जूझ रहे लोगों में भारत पहले स्थान पर होगा।

विशेषज्ञ कहते हैं कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग व गठिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ाता है। यही वजह है कि वजन कम करने या उसे काबू करना जरूरी हो जाता है। पर, इसका अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे-समझे तेजी से वजन घटाने (रैपिड वेट लॉस) की प्रक्रिया में सेहत को खतरे में डाला जाए।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में छपे एक अध्ययन के अनुसार बिना सोचे-समझे और विशेषज्ञ से परामर्श किए बिना तेजी से वजन कम करना शरीर के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है।

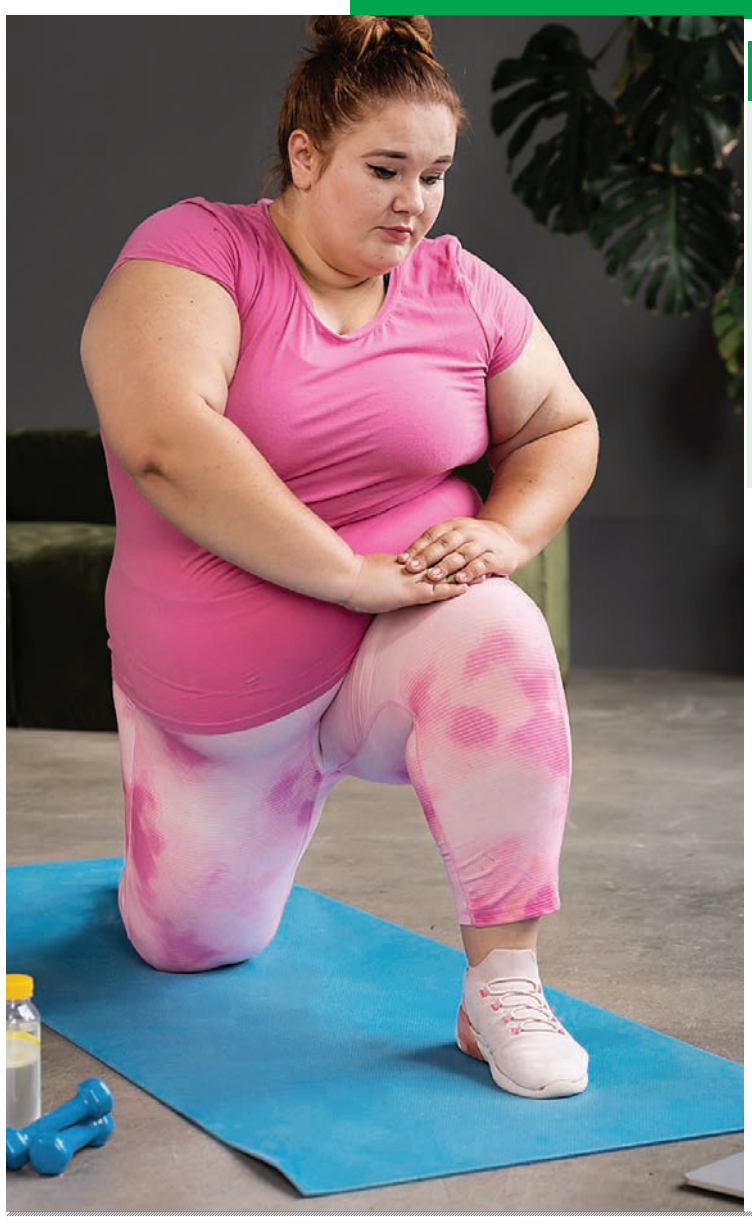

आयुर्वेद देता है जीवनशैली के संतुलन पर जोर

आयुर्वेद के अनुसार मोटापा त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) के असंतुलन तथा अग्नि की विषमता से उत्पन्न होता है। पाचन ठीक न हो पाने से कफ दोष पर विशेष असर पड़ता है। त्रिदोष के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति और अग्नि अलग होती है। इसी के आधार पर आहार और जीवनशैली का संतुलन रखना शरीर को भी स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम व मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी है।

- कैफीन का उपयोग कम से कम करें
- विरुद्ध आहार जैसे दूध और फल, मछली और दूध, नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।
- खाना हल्का गर्म व ताजा ही खाएं।
- पर्याप्त पानी पिएं। उम्र, मौसम और शारीरिक श्रम के अनुसार यह मात्रा बढ़ सकती है। भोजन के तुरंत बाद बहुत सारा पानी न पिएं।
- शारीरिक बल, क्षमता के अनुसार व्यायाम व योग करना चाहिए।

डाइटिंग के नुकसान भी समझें

खास तरह के डाइट प्लान जैसे क्रैश डाइट, वेगन डाइट व कीटो डाइट आदि का पालन करने से कुछ समय के लिए वजन तेजी से कम होता है। किसी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होती है। किसी में वसा कम करके प्रोटीन पर जोर दिया जाता है। कुछ डाइट्स में कैलोरीज को काफी अधिक प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ऐसे में मेटाबॉलिक दर धीमी हो सकती है, जिससे लंबे समय के बाद वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही डाइट छोड़ते ही वजन फिर बढ़ जाता है।

कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार (जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन 100 ग्राम से कम हो) शरीर में सूजन बढ़ा सकता है। हड्डियां कमजोर व यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। इसी तरह वसा पूरी तरह बंद करने से शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के की कमी हो सकती है। अपने डॉक्टर से पोषण संबंधी जरूरतों को जरूर समझें। इस तरह वजन कम करें कि वसा कम हो, पर मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी न आए और शरीर को पोषक तत्व मिलते रहें।

कितना वजन कम करना सही

प्रति सप्ताह 0.5-1 किग्रा वजन कम करना या प्रति माह 2 से 4 किग्रा वजन कम करना उचित है। वजन घटाने की इस दर को अधिकतर अध्ययनों ने सुरक्षित माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति हर हफ्ते लगभग 150 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाले और लगभग 75 मिनट तक उच्च तीव्रता वाले व्यायाम कर सकता है। चूंकि, हर व्यक्ति की जैविक घड़ी या सर्केडियन रिद्म अलग होती है, ऐसे में शारीरिक क्षमता के संबंध में डॉक्टर से बात जरूर करें।

दीर्घकाल को ध्यान में रखकर करें कोशिशें

- **लक्ष्य :** आप क्यों वजन कम करना चाहते हैं? सौंदर्य नहीं सेहत को लक्ष्य बनाएं। मांसपेशियों की सेहत का ध्यान रखें।
- **शरीर को समझें :** हमारे शरीर का वजन से जुड़ा सेटिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वजन कम करना नुकसान कर सकता है या फिर से वजन बढ़ने लगता है।
- **जेनेटिक कारण और जीवनशैली :** मोटापा आनुवंशिक, गलत खानपान, निष्क्रिय जीवनशैली व नींद की कमी से भी बढ़ता है। इसका ध्यान रखें।
- **दवाएं :** कुछ दवाएं हैं, जो वजन कम करने का दावा करती हैं, इन्हें विशेषज्ञ की सलाह से ही लें।

ये जड़ी-बूटियां भी फायदेमंद

- **पुनर्नवा :** शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में सहायक है। जरूरी मिनरल्स व इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, जिंक आदि का संतुलन भी बना रहता है। आप पुनर्नवा की चाय पी सकते हैं।
- **त्रिकटु चूर्ण :** सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली तीनों बराबर मिलाकर चूर्ण बना लें। आधा चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी से ले लें।
- **विजयसार :** इस वृक्ष की छाल में वसा कम करने वाले गुण होते हैं, जिनसे पेट पर संचित वसा कम करने में मदद मिलती है।
- **गुग्गुल :** यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में सहायक है।
- **मेथी :** मेथी पाचन तंत्र के लिए लाभप्रद है। इससे शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। पेट देर तक भरे रहने का एहसास होता है।

क्या हो सकते हैं नुकसान

- मेटाबॉलिज्म धीमा होना।
- शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
- मांसपेशियों की कार्य क्षमता में कमी व ऐंठन बढ़ना। हड्डियों पर बुरा असर।
- कमजोरी और थकान महसूस होना।
- डिहाइड्रेशन हो सकता है।
- पित्त की पथरी का जोखिम बढ़ना।
- रोग प्रतिरोधक तंत्र का कमजोर होना।
- इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन।
- बाल झड़ना, गुस्सा व बेचैनी बढ़ना।
- कुपोषण की समस्या।

शक्ति की उपासना और स्वास्थ्य का महासंगम : नवरात्रि व्रत में कैसे रहें ऊर्जावान

व्रत की प्रासंगिकता और जीवन की चुनौतियां

चैत्र नवरात्रि का महापर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यह नौ दिन 'शक्ति' की आराधना के साथ-साथ स्वयं के आत्म-निरीक्षण और शरीर के शुद्धिकरण का भी समय होता है। सनातन परंपरा में व्रत या उपवास को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देखा गया है, जो शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। हालांकि, आज के भागदौड़ भरे जीवन और बदलते खान-पान के तौर-तरीकों के कारण, कई श्रद्धालु इस पावन काल में अपनी सेहत के साथ अनजाने में खिलवाड़ कर बैठते हैं। श्रद्धा के अतिरेक में पूरे दिन भूखे रहना और फिर रात को भारी, तैलीय फलाहार लेना मेटाबॉलिज्म के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसी विषय की गंभीरता को देखते हुए, राजधानी चौपाल ने देश की विख्यात सीनियर क्लीनिकल डाइटीशियन और 'वनडाइटटुडे' की संस्थापक डॉ. अनु अग्रवाल से विशेष चर्चा की है।

मेटाबॉलिज्म और व्रत का गहरा वैज्ञानिक संबंध

डॉ. अनु अग्रवाल के अनुसार, व्रत के दौरान शरीर की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल जाती है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर ऊर्जा के लिए संचित वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। यदि इस प्रक्रिया को सही आहार के साथ व्यवस्थित किया जाए, तो यह 'वेट लॉस' और 'बॉडी डिटॉक्स' का बेहतरीन जरिया बनता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम 'सैटायटी' (तृप्ति) की कमी के कारण शाम को अचानक कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर भोजन करते हैं। इससे इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ता है, जिससे थकान, सुस्ती और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सही प्लानिंग से किया गया व्रत न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को वह जरूरी आराम भी प्रदान करता है जिसकी उसे लंबे समय से आवश्यकता थी।

ऊर्जा बनाए रखने के सात अचूक मंत्र

व्रत के दौरान ऊर्जावान रहने के लिए आहार में विविधता और संतुलन अनिवार्य है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी 'व्रत की थाली' में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाना। अक्सर व्रत में लोग केवल आलू या साबूदाना खाते हैं, जो केवल कैलोरी बढ़ाते हैं। इसके बजाय, पनीर, दही, मखाना और मूंगफली जैसे प्रोटीन स्रोतों को शामिल करें। दूसरा नियम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव। कुट्टू और राजगिरा का आटा इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये अनाज धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे शरीर को पूरे दिन निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है और अचानक शुगर गिरने का खतरा कम हो जाता है। फाइबर के लिए सेब, खीरा और पपीता जैसे फलों का सेवन बढ़ाना चाहिए, जो पाचन को सुचारू रखते हैं।

हाइड्रेशनः शरीर का मुख्य ईंधन

मार्च के इस महीने में बढ़ती गर्मी के बीच हाइड्रेशन सबसे बड़ी चुनौती है। डॉ. अग्रवाल स्पष्ट करती हैं कि व्रत के दौरान पानी की जरूरत सामान्य दिनों से अधिक हो जाती है। केवल प्यास लगने पर पानी पीना पर्याप्त नहीं है। एक साथ

बहुत सारा पानी पीने के बजाय दिनभर 'सिप-सिप' करके पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कोशिकाओं के बीच सिग्नल भेजने का काम करते हैं। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी महसूस हो सकती है। नारियल पानी, ताजी छाछ और नींबू पानी इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं। पैक्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद अत्यधिक चीनी ग्लूकोज को अचानक बढ़ाकर बाद में थकान पैदा कर सकती है।

कमजोरी और लो-बीपी का त्वरित प्रबंधन

व्रत के दौरान कुछ लोगों को अचानक चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा छाने जैसी शिकायतें होती हैं। यह अक्सर 'हाइपोग्लाइसीमिया' (शुगर का कम होना) या लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए। बैठने या लेटने से मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और गिरने का जोखिम कम हो जाता है। त्वरित ऊर्जा के लिए केला या दो खजूर जैसे 'क्विक एनर्जी फूड्स' लेने चाहिए। यदि आप लंबे समय से भूखे हैं, तो तुरंत भारी भोजन करने के बजाय पहले नींबू पानी या नारियल पानी लें। डॉ. अग्रवाल का सुझाव है कि यदि लगातार घबराहट या सीने में भारीपन महसूस हो, तो इसे सामान्य थकान न मानकर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए।

फ्राइड फूड और स्वास्थ्य के बीच का संघर्ष

नवरात्रि में बाजारों में मिलने वाले 'फलाहारी' चिप्स, कुट्टू की पूड़ियां और साबूदाना वड़ा स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। डॉ. अग्रवाल के अनुसार, डीप फ्राई करने से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। उच्च वसा वाले भोजन को पचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे खाने के बाद भारीपन और नींद आने लगती है। साथ ही, बार-बार तेल गर्म करने से उसमें 'फ्री रेडिकल्स' पैदा होते हैं, जो शरीर में 'ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस' बढ़ाते हैं। यह न केवल आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इंसुलिन की संवेदनशीलता को भी कम कर देता है, जो भविष्य में मेटाबॉलिक रोगों का कारण बन सकता है।

सावधानी और विशेष श्रेणी के लिए निर्देश

व्रत हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों को व्रत के दौरान अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह, हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) के रोगियों में नमक और पानी के असंतुलन से बीपी अचानक बढ़ या घट सकता है। थायराइड और हार्मोनल असंतुलन वाले व्यक्तियों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उपवास उनके मेटाबॉलिक रेट को और अधिक प्रभावित कर सकता है। बुजुर्गों के मामले में, प्यास का अहसास कम होने के कारण वे जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे सभी संवेदनशील समूहों को व्रत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

संयमित जीवन और सफल उपवास

राजधानी चौपाल के माध्यम से हम अपने सभी पाठकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि नवरात्रि का उपवास केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने का समय है। दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम या योगासन से करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। दोपहर में 15-20 मिनट का छोटा विश्राम आपकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। स्क्रीन टाइम कम रखें और पर्याप्त नींद लें। यदि आप इन वैज्ञानिक और पोषण संबंधी बातों का ध्यान रखेंगे।

नवरात्रि व्रत में शक्ति और भक्ति का संगम हैं ये 'फलाहारी लड्डू'

नवरात्रि में शुद्धता सर्वोपरि है। लड्डू बनाने से पहले रसोई को स्वच्छ करें और स्नान के पश्चात ही भोग तैयार करें। इन लड्डुओं को आप कांच के एयरटाइट जार में भरकर पूरे 9 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस बार बाजार की मिलावटी मिठाइयों के बजाय, अपने हाथों से तैयार इस 'फलाहारी प्रसाद' का आनंद लें। यह न केवल आपके व्रत को सफल बनाएगा, बल्कि परिवार के बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी वरदान साबित होगा।

चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा देश शक्ति की उपासना में लीन है, वहीं व्रतधारियों के लिए खान-पान का विशेष महत्व होता है। नौ दिनों के उपवास में शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना और माता रानी को शुद्ध सात्विक भोग लगाना, हर भक्त की प्राथमिकता होती है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी, जो न केवल स्वाद में बेमिसाल है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है।

सेहत और सरोकारः क्यों खास हैं सिंघाड़ा-मखाना लड्डू?

अक्सर व्रत के दौरान लोग तली-भुनी चीजों का अधिक सेवन करते हैं, जिससे सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। 'राजधानी चौपाल' के पाठकों के लिए यह रेसिपी एक 'पावर बूस्टर' का काम करेगी।

- **सिंघाड़े का आटाः** यह ठंडी तासीर का होता है और इसमें आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह थायराइड और दिल की सेहत के लिए रामबाण है।
- **मखाना (फॉक्स नट्स):** मखाना कैल्शियम का भंडार है। यह हड्डियों को मजबूती देता है और व्रत में होने वाली कमजोरी को दूर कर तुरंत एनर्जी प्रदान करता है।
- **देसी खांडः** चीनी की जगह देसी खांड का प्रयोग इसे पूरी तरह सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है, जिससे शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है।

भोग की थालीः सामग्री की सूची

माता रानी के नैवेद्य के लिए आपको चाहिए:

- **सिंघाड़े का आटाः** 2 कप (ताजा पिसा हुआ श्रेष्ठ रहता है)
- **फूल मखानेः** 1 कप (अच्छी गुणवत्ता वाले)
- **शुद्ध देसी घीः** 3 बड़े चम्मच (गाय का घी)
- **देसी खांड या बूराः** 1/2 कप (मिठास स्वादानुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं)
- **इलायची पाउडरः** 1/4 छोटा चम्मच (खुशबू और पाचन के लिए)

पाक कलाः कदम-दर-कदम बनाने की विधि

इस मिठाई की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। इसे बनाने में कम समय लगता है और यह लंबे समय तक खराब नहीं होते।

- **मखानों का कुरकुरापन :** सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही (लोहे या पीतल की हो तो बेहतर) लें। इसमें एक चम्मच घी डालकर हल्का गर्म करें। मखाने डालें और धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक वे हाथ से दबाने पर टूटने न लगें। इन्हें निकालकर अलग रख दें।
- **आटे की सोंधी खुशबू :** उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें। अब सिंघाड़े का आटा डालकर गैस की लौ धीमी रखें। इसे लगातार चलाते रहें। जैसे ही आटे का रंग हल्का बादामी होने लगे और रसोई सोंधी खुशबू से महक उठे, समझ जाएं कि आटा भुन चुका है।
- **मखानों का दरदरा मिश्रण :** भुने हुए मखानों को मिक्सी में केवल एक बार 'पल्स' मोड पर चलाएं या खलबट्टे में कूट लें। ध्यान रहे, हमें मखानों का पाउडर नहीं, बल्कि दरदरा हिस्सा चाहिए, जो लड्डू खाते समय दांतों के नीचे क्रंच (कुरकुरापन) पैदा करे।
- **मिश्रण का मेल :** भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में निकालें। जब यह छूने लायक हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसमें देसी खांड, दरदरे मखाने और इलायची पाउडर मिलाएं। यदि मिश्रण सूखा लगे, तो ऊपर से एक चम्मच पिघला हुआ घी और डाल सकते हैं।
- **आकार और स्वरूप :** अपनी हथेलियों को घी से चिकना करें और छोटे-छोटे गोल लड्डू तैयार करें। आप चाहें तो इनके ऊपर आधा कटा हुआ बादाम या पिस्ता भी सजावट के लिए लगा सकते हैं।

— जय माता दी!

भारत का अभेद्य चक्रव्यूहः 'नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर' के युग में महाशक्ति बनने की तैयारी

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| वैश्विक कूटनीति और युद्ध के बदलते स्वरूप ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ अब जीत सीमाओं पर सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीक की मारक क्षमता से तय होती है। ईरान-इजरायल के बीच छिड़ी जंग और आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन्स के बढ़ते आतंक के बीच भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव का बिगुल फूंक दिया है। भारत अब 'नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर' यानी बिना आमने-सामने आए दुश्मन को धूल चटाने वाली अत्याधुनिक तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। संसद में पेश रक्षा समिति की हालिया रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है जिसे भेदना नामुमकिन होगा।

भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए छह बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है, जिनके लिए 2,19,306.47 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है। यह निवेश केवल हथियारों की खरीद भर नहीं है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत वैश्विक रक्षा राजनीति में अपनी धाक जमाने की एक दूरगामी रणनीति है।

अनंत शस्त्र और स्वदेशी एस-400ः सुरक्षा का दोहरा कवच : आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और मिसाइलें हैं। इसका तोड़ भारत ने 'अनंत शस्त्र' के रूप में निकाला है। यह एक 'क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल' सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन झुंड को पलक झपकते ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही, रूस के एस-400 की तर्ज पर भारत अपना खुद का 'लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल' सिस्टम विकसित कर रहा है। यह लंबी दूरी का सुरक्षा कवच दुश्मन के विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही हवा में राख कर देने की क्षमता रखेगा।

ऑपरेशन सिंदूर और रक्षा बजट में ऐतिहासिक उछाल : 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' की शुरुआत की थी। 6 मई 2025 से निरंतर चल रहे इस ऑपरेशन ने भारतीय रक्षा तंत्र को यह अहसास कराया कि आधुनिक चुनौतियों के लिए बजट की सीमाओं को तोड़ना होगा। यही कारण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष रक्षा बजट में पिछले 10 साल की सबसे बड़ी वृद्धि की है। तीनों सेनाओं के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इसमें से 64,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा केवल फाइटर जेट्स और शक्तिशाली स्वदेशी इंजनों के विकास के लिए सुरक्षित रखा गया है।

साइबर स्पेस और समुद्र की गहराई में भारत की धाक : नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का एक बड़ा हिस्सा अदृश्य होता है। डीआरडीओ के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित हथियारों और साइबर डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है। भारत एक ऐसा 'साइबर कवच' तैयार कर रहा है जो दुश्मन के डिजिटल हमलों को न केवल रोकेगा, बल्कि उनके सिस्टम को पंगु बनाने की क्षमता भी रखेगा।

समुद्र के भीतर भी भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। नौसेना के लिए 'एडवांस्ड टॉरपीडो डिफेंस सिस्टम' और 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' विकसित किए जा रहे हैं, ताकि हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो सके। इसके अलावा अस्त्र, नाग और ध्रुवास्त्र जैसी प्रसिद्ध मिसाइलों के मार्क-II वेरिएंट्स पर भी युद्धस्तर पर काम जारी है।

छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का स्वप्न अब हकीकत की ओर

रक्षा क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी छलांग 'नेक्स्ट जेनरेशन' के लड़ाकू विमानों की तैयारी है। अब तक भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, 'एएमसीए' (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम शुरू हो गया है। ये विमान केवल लड़ाकू विमान नहीं होंगे, बल्कि 'उड़ते हुए कमांड सेंटर' की तरह काम करेंगे। इनमें हाइपरसोनिक गति और उन्नत सी4आईएसआर सिस्टम होगा, जो युद्धक्षेत्र में तैनात अन्य ड्रोन्स और मिसाइलों को दिशा-निर्देश देने में सक्षम होगा। एएमसीए अब ड्राइंग बोर्ड से निकलकर विकास के चरण में पहुँच चुका है, और सरकार इसके निर्माण की जिम्मेदारी तय करने के अंतिम दौर में है।

भविष्य की चुनौती और रक्षा दृष्टिकोण

संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, भारत का नया रक्षा दृष्टिकोण आक्रामक और रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के बीच एक सटीक संतुलन बनाने पर केंद्रित है। भारत अब यह समझ चुका है कि कल के युद्ध महज गोलियों से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम और फ्रीक्वेंसी से लड़े जाएंगे। 2026-27 के लिए आवंटित 2.19 लाख करोड़ रुपये का निवेश इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह बजट पिछले वर्ष के अनुमान से लगभग 22% अधिक है, जो स्पष्ट करता है कि भारत अब वैश्विक रक्षा मंच पर 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका निभाने को तैयार है।

मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप

इन पर 2200 सैनिक मौजूद, दावा-खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान

वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। CNN के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि 3 अमेरिकी वॉरशिप के साथ मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं।

इनमें USS त्रिपोली, USS सैन डिएगो, USS न्यू ऑरलियंस शामिल हैं। इन पर करीब 2200 सैनिक तैनात हैं। ये सभी सैनिक 31ST मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट (MEU) का हिस्सा हैं, जिसे तुरंत एक्शन के लिए तैयार रखा जाता है।

इनमें से USS त्रिपोली एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी ऐसा युद्धपोत जो मरीन सैनिकों, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों (जैसे F-35B) को लेकर चलता है। ये तीनों वॉरशिप जापान के पास थे। अभी यह भारत के पास दक्षिणी हिंद महासागर में है।

अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प सरकार ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसे घेरने (ब्लॉकेड) की योजना पर विचार कर रही है।

अगले सप्ताह नए स्टेज में पहुंच सकता है ईरान जंग

अमेरिका की तैयारियों से लग रहा है कि ईरान जंग अगले हफ्ते नए स्टेज में पहुंच सकता है। इससे पहले कई बार ट्रम्प यह कह चुके हैं कि वे मिडिल ईस्ट में सैनिक नहीं भेज रहे हैं। ट्रम्प ने गुरुवार को कहा था, "मैं कहीं भी सैनिक नहीं भेज रहा हूं। अगर भेजता भी, तो आपको नहीं बताता।"

ट्रम्प अपने अचानक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके बयान से पता नहीं चल रहा कि वे क्या करने वाले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ट्रम्प ईरान में कार्रवाई तेज करने के लिए हजारों सैनिक भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं

पहली वजह- होर्मुज को फिर से खोलना : दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने यहां जहाजों की आवाजाही लगभग रोक दी है, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

पिछले कुछ दिनों में ट्रम्प ने अपने सहयोगी देशों से भी होर्मुज में युद्धपोत भेजने को कहा, लेकिन किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। ऐसे में USS त्रिपोली और बाकी वॉरशिप पर मौजूद अमेरिकी मरीन उनके लिए सबसे अहम विकल्प बन सकते हैं।

अगर अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित करना चाहता है, तो उसे ईरान के तटीय इलाकों में सैनिक उतारने पड़ सकते हैं। ईरान की नौसेना को काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए यह विकल्प अमेरिका के लिए संभव और कम जोखिम वाला माना जा रहा है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि USS त्रिपोली पर मौजूद मरीन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान के दक्षिणी तट के पास स्थित द्वीपों पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। इन द्वीपों को आगे रणनीतिक ठिकाने या दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर संभावित हमलों को रोका जा सके।

ईरान के लिए बहुत खास है खार्ग आइलैंड

खार्ग द्वीप ईरान के तट से करीब 15 मील दूर है और यहीं से उसके करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है। इसलिए अगर अमेरिका इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेता है या वहां नाकाबंदी करता है, तो वह ईरान पर होर्मुज को खोलने का दबाव बना सकता है।

हालांकि इस योजना में बड़ा जोखिम भी है। अगर अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करता है, तो उसके सैनिक सीधे हमलों के दायरे में आ जाएंगे और यह जरूरी नहीं कि ईरान इससे झुक जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को सीधे ईरान की जमीन या खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वह अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर सकता है, ताकि तेल ले जाने वाले जहाजों को रास्ते में सुरक्षा दी जा सके।

दूसरी वजह- ईरान के यूरेनियम पर कब्जा : दूसरा बड़ा कारण है ईरान का अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम। ईरान के पास करीब 950 पाउंड यूरेनियम ऐसा है जिसे परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह यूरेनियम उन ठिकानों के मलबे में दबा है, जिन पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। इसे सुरक्षित करने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने की जरूरत पड़ेगी।

28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद ट्रम्प के बयान बदलते रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है। वे चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। USS त्रिपोली की अहमियत यहीं सामने आती है। इस जहाज पर 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2200 सैनिक सवार हैं, जो जापान के ओकिनावा में तैनात रहते हैं। ये सैनिक जमीन और हवा दोनों तरह की लड़ाई, छापेमारी और समुद्र से जमीन पर उतरने वाले ऑपरेशन में माहिर होते हैं। USS त्रिपोली एक ऐसा वॉरशिप है जो समुद्र से ही हवाई और जमीनी ऑपरेशन चला सकता है। इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर और सैनिकों को किनारे तक पहुंचाने वाले विशेष जहाज मौजूद हैं।

अगले हफ्ते वॉर जोन में पहुंचेगा USS त्रिपोली, मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा अमेरिका

उम्मीद है कि USS त्रिपोली अगले हफ्ते वॉर जोन में पहुंच जाएगा। अगर ट्रम्प जमीन पर सैनिक भेजने का फैसला लेते हैं, तो यह पिछले दो दशकों में पहली बार होगा जब अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध में उतारे जाएंगे इस वॉरशिप का नाम 1805 में त्रिपोली के खिलाफ अमेरिका की जीत की याद में रखा गया था। यह पहली बार था जब अमेरिका ने विदेशी जमीन पर जीत हासिल कर अपना झंडा फहराया था। अमेरिका ने 28 फरवरी से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू की है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस समय अरब सागर में तैनात है, जिसमें USS फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर और USS स्प्रूअंस जैसे मिसाइल डेस्ट्रॉयर शामिल हैं। इसके अलावा पांच अन्य मिसाइल डेस्ट्रॉयर भी इलाके में अलग-अलग तैनात हैं। जेराल्ड आर. फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले लाल सागर में था, लेकिन इसका मुख्य जहाज USS जेराल्ड आर. फोर्ड अब ग्रीस के सूडा बे जा रहा है। इस जहाज में पिछले हफ्ते आग लग गई थी। इसके बाद उसकी मरम्मत होगी। इसके साथ USS बैनब्रिज, USS माहन और USS विंस्टन एस. चर्चिल जैसे जहाज हैं। पूर्वी मैडिटेरिन सी में भी तीन अमेरिकी मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात हैं। इसी बीच USS गोंजालेज नाम का एक डेस्ट्रॉयर अमेरिका के नॉरफोक बेस से रवाना हुआ है। यह कहां तैनात होगा, अभी पता नहीं है, लेकिन संभावना है कि इसे मिडिल ईस्ट या किसी अन्य अहम इलाके में भेजा जा सकता है।

पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की : मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की

कहा- समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। पीएम ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातकर उन्हें ईद और नवरोज की बधाई दी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी।

पीएम ने लिखा- मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पजशकियान से बात की। हमने उम्मीद जताई कि इस त्योहार के समय मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता आए।

मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत में मिडिल ईस्ट में जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर (जैसे तेल, बिजली आदि) पर हो रहे हमलों की निंदा की, क्योंकि इससे इलाके की शांति और दुनिया की सप्लाई पर असर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, ताकि व्यापार ठीक से चलता रहे। इसके साथ ही, ईरान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में मदद के लिए ईरान का धन्यवाद किया। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरानी लोगों को नवरोज की बधाई दी थी और रूस को ईरान का सच्चा दोस्त बताया था।

60 साल में पहली बार अल-अक्सा मस्जिद ईद में बंद

ईरान में बाजार सूने; यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर रोक

तेल अवीव/तेहरान (राजधानी चौपाल)| दुनियाभर में आज ईद मनाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से जंग चल रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। 1967 के अरब-इजराइल युद्ध के बाद पहली बार है, जब अल-अक्सा को पूरी तरह बंद किया गया है। यह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।

ईरान में शुक्रवार को ईद मनाया गया। इस मौके पर बाजार वीरान नजर आए। वहीं कतर, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाया जा रहा है। जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। ईरान में इस बार ईद उल फित्र का त्योहार जंग और तनाव के साये में मनाया गया। रमजान खत्म होने के बाद देशभर में लोगों ने मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा की। युद्ध और हमलों के कारण कई जगहों पर जश्न सादगी से मनाया गया। बाजारों में भी रौनक कम रही और कई दुकानें बंद दिखीं।

28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध के बाद, सुरक्षा कारणों से इजराइली अधिकारियों ने यरुशलम में आम लोगों की एंट्री बंद कर रखी है। सिर्फ वहां रहने वाले लोग या दुकानदार ही अंदर जा सकते हैं। 6 मार्च से वेस्टर्न वॉल, अल-अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जैसे सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पूरे देश में भीड़ पर भी पाबंदी है। मस्जिद के अंदर 100 और बाहर 50 लोगों तक ही इकट्ठा होने की अनुमति है। यरुशलम के पुराने शहर के गेट पर शुक्रवार को ईद-उल-फित्र की नमाज के दौरान सैकड़ों मुस्लिम नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। नमाजी 'अल्लाहु अकबर' और कलमा पढ़ते हुए गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती हटाया।

UAE में ईद-उल-फितर के मौके पर शुक्रवार से सोमवार तक 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूरे देश में बाजार, मॉल और सार्वजनिक जगहों पर लाइटिंग और सजावट की गई और लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है।

ईराक में इस बार ईद उल फितर डर और तनाव के माहौल में मनाई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां के लोगों की भी जिंदगी पर हुआ है। बाहर का माहौल पहले जैसा नहीं है। बड़े आयोजन और भीड़-भाड़ वाले जश्न अब कम हो गए हैं। लोग भीड़ से बच रहे हैं और बाहर निकलने में सावधानी बरत रहे हैं। पहले जहां बच्चे मोहल्लों में घूमकर ईदी इकट्ठा करते थे, अब ऐसे नजारे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा चिंता ज्यादा है।

लेबनान में ईद के मौके पर अलग-अलग माहौल है। उत्तरी लेबनान में जहां एक तरफ लोग ईद-उल-फितर की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दक्षिण लेबनान में हजारों शरणार्थी अपने घरों से दूर रहकर ईद मना रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद लेबनान के दक्षिणी शहरों में भी हमले तेज कर दिए हैं। अब तक यहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

रूस में ईद-उल-फितर शुक्रवार को मनाई गई। उस दिन मॉस्को की 4 मस्जिदों में 2 लाख से ज्यादा लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। रूस में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईद-उल-फितर के मौके पर देश के मुसलमानों को बधाई दी।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)